VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

का सारांश

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची

Building Mental Resilience for UPSC CSE with VisionIAS Student Wellness Cell

The UPSC Civil Services Examination is one of the most prestigious exams in the country, bringing immense professional and personal satisfaction. However, the journey often involves overcoming loneliness, intense competition pressure, anxiety, and other psychological challenges. These issues can impact both your preparation and overall well-being.

At **VisionIAS**, we recognize the multifaceted nature of this journey. To support our students comprehensively, we have established a dedicated Student Wellness Cell. Since April 2024, our highly professional psychologists and experienced professionals have provided confidential and mindful support as per student needs.

From Stress Management to Academic Excellence

Enhancing Academic Performance: Effective stress management contributes to better academic outcomes.

Professional Mental Health Support: Seeking professional help is crucial for success in UPSC preparation.

Well-Supported Mind for Excellence: Mental well-being is essential for achieving success in UPSC exams.

Comprehensive Wellness Cell: Addressing various issues impacting mental health and academic performance.

Safe and Non-Judgmental Environment: A space for students to discuss issues and receive personalized support.

Confidential and Structured Support: Multiple, structured sessions based on the severity of the issues.

Common Issues and Our Approach

Our counseling services have addressed a variety of issues, including:

Anxiety and Hopelessness: Using Cognitive Behavioural Therapy (CBT) to promote positive thinking.

Lack of Motivation and Focus: Introducing time management strategies and SMART goal-setting.

Emotional Struggles: Providing a safe space for expression and techniques such as journaling and progressive muscle relaxation.

Social Isolation and Loneliness: Encouraging healthy social interactions and setting personal boundaries.

Family and Personal Issues: Offering advice on coping with family dynamics, personal loss, and significant life stressors.

Scan the QR code for more details

To support the larger student community, **VisionIAS** is now extending our counseling and wellness support to all students preparing for UPSC CSE, regardless of their coaching institute affiliation. Schedule a session by visiting our office at Apsara Arcade near Karol Bagh Metro Station or emailing ***student.wellness@visionias.in.***

Remember, seeking help is a sign of strength, not weakness.

विषय सूची

1. बदलती विश्व व्यवस्था की गतिशीलता (Dynamics Of Changing World Order).....5

1.1. भारत की आर्थिक कूटनीति 5
1.2. भू-राजनीति में प्रौद्योगिकी की भूमिका 5
1.3. आपदा राहत कूटनीति 6
1.4. पैरा-डिप्लोमेसी 6
1.5. भारत की सामरिक स्वायत्तता 7
1.6. भारत: द वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ 8
1.7. भारत और विकासात्मक सहयोग 8
1.8. सॉफ्ट पॉवर और सांस्कृतिक कूटनीति 9
1.9. भारतीय डायस्पोरा 9
1.10. बंदरगाहों का भू-राजनीतिक महत्त्व 10
1.11. सामरिक उपकरण के रूप में क्रूड ऑयल 10

2. भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और समझौते (REGIONAL, AND GLOBAL GROUPINGS AND AGREEMENTS INVOLVING INDIA AND/OR AFFECTING INDIA'S INTEREST) 11

2.1. भारत और G20 11
2.2. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा 11
2.3. अफ्रीकी संघ: G20 का एक स्थायी सदस्य 12
2.4. ब्रिक्स का विस्तार 12
2.5. भारत और हिंद-प्रशांत 13
2.6. इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) ..14
2.7. क्वाड 14
2.8. भारत-आसियान संबंध 15
2.9. राष्ट्रमंडल 16
2.10. गुटनिरपेक्ष आंदोलन 16

3. भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध (INDIA AND ITS NEIGHBOURHOOD RELATIONS) 17

3.1. भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी 17
3.2. चीन का उदय और भारत के लिए खतरा 17
3.3. भारत-चीन सीमा विवाद 18
3.4. सीमापारीय नदी जल प्रबंधन 19
3.5. भारत-नेपाल संबंध 19
3.6. भारत-भूटान संबंध 20
3.7. तालिबान शासन के तहत भारत-अफगानिस्तान संबंध 21
3.8. भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित पड़ोसी देश 21
3.9. भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा रेखा 22
3.10. भारत-मालदीव संबंध 23
3.11. दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) 23

4. भारत को शामिल करने वाले और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समूह तथा समझौते (Bilateral Grouping and Agreements Involving India and/or Affecting India) 25

4.1. अब्राहम समझौता 25
4.2. इज़रायल-फ़िलिस्तीन युद्ध 25
4.3. भारत-इजराइल संबंध 26
4.4. भारत-संयुक्त अरब अमीरात (UAE) संबंध 26
4.5. भारत-सऊदी अरब संबंध 27
4.6. भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) संबंध 27
4.7. भारत और पांच मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs) के संबंध ...28
4.8. भारत-दक्षिण कोरिया संबंध 28
4.9. भारत-इंडोनेशिया संबंध 29
4.10. दक्षिण चीन सागर 29
4.11. भारत-अमेरिका संबंध 30
4.12. भारत-कनाडा संबंध 30
4.13. भारत- लैटिन अमेरिका संबंध 31
4.14. भारत-यूरोपीय संघ संबंध 31
4.15. भारत-रूस संबंध 32
4.16. भारत-फ्रांस संबंध 32
4.17. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध 33
4.18. भारत-इटली संबंध 33
4.19. भारत नॉर्डिक संबंध 33
4.20. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध 34
4.21. भारत-अफ्रीका संबंध 35
4.22. भारत-मॉरीशस संबंध 35

5. भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव (Effect of Policies and Politics of Developed and Developing Countries on India's Interests) 36

5.1. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव - दसवीं वर्षगांठ 36
5.2. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) 36
5.3. नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) 37
5.4. ऑकस 37

6. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश (IMPORTANT INTERNATIONAL INSTITUTIONS, AGENCIES, AND FORA, THEIR STRUCTURE, MANDATE) ...38

6.1. बदलते समय में वैश्विक संस्थाएं 38
6.2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: एक नज़र में 39
6.3. भारत और यू.एन. पीसकीपिंग यानी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना 39
6.4. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद: एक नजर में 40
6.5. भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC) 41
6.6. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) 41

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

आपकी सहायता के लिए, हमने VisionIAS मेन्स 365 स्टडी मटेरियल से आवश्यक जानकारी का संकलन कर मेन्स 365 डॉक्यूमेंट का सारांश तैयार किया है। जैसा कि आप सभी को पता है VisionIAS मेन्स 365 स्टडी मटेरियल करेंट अफेयर्स के व्यापक कवरेज के लिए प्रसिद्ध है।

Mains 365 अंतर्राष्ट्रीय संबंध डॉक्यूमेंट के सारांश में UPSC मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का व्यापक अवलोकन प्रदान किया गया है। साथ ही, इन घटनाक्रमों के महत्त्व व संबंधित सरोकारोंआदि को भी इसमें शामिल किया गया है।

यह डॉक्यूमेंट आपको प्रमुख टॉपिक को जल्दी और प्रभावी ढंग से रिवाइज करने में मदद करेगा।

इस डॉक्यूमेंट को इन्फोग्राफिक प्रारूप में डिजाइन किया गया है, जिससे आप इसमें दी गई जानकारी को आसानी से उत्तर लेखन में शामिल कर सकते हैं।

अपनी तैयारी में सुधार करने और UPSC मेन्स में अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए इन जानकारियों का उपयोग कीजिए।

1. बदलती विश्व व्यवस्था की गतिशीलता (Dynamics Of Changing World Order)

1.1. भारत की आर्थिक कूटनीति

परिभाषा: आर्थिक कूटनीति विदेश नीति का एक साधन है जिसमें देश के **आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक हितों की पूर्ति** के लिए **अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिचालन में आर्थिक साधनों का उपयोग** किया जाता है।

निष्कर्ष

आर्थिक कूटनीति को **प्रतिस्पर्धा और सहयोग, आकांक्षाओं और प्राप्य लक्ष्यों तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के बीच संतुलन** बनाना चाहिए।

1.2. भू-राजनीति में प्रौद्योगिकी की भूमिका

प्रौद्योगिकी भू-राजनीति को कैसे प्रभावित करती है

- राज्य की **संप्रभुता (भौतिक और क्षेत्रीय) की पारंपरिक अवधारणा** को चुनौती देती है
- **राष्ट्र की आर्थिक शक्ति** को आकार दे सकती है
- **वैश्विक मंच पर प्रभाव** डालने में मदद करता है
- **जनमत, चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं**

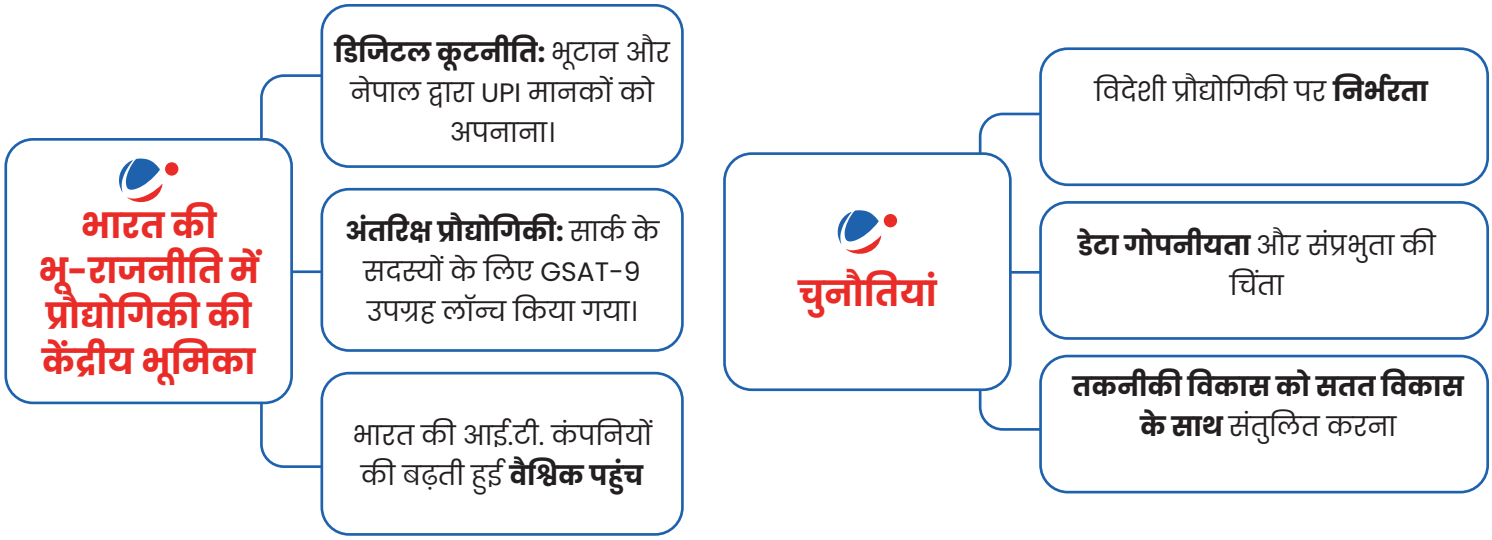

1.3. आपदा राहत कूटनीति

आपदा राहत कूटनीति से तात्पर्य 'प्राकृतिक/ मानव जनित आपदाओं या संघर्षों से प्रभावित अन्य देशों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए एक देश के प्रयासों' से है।

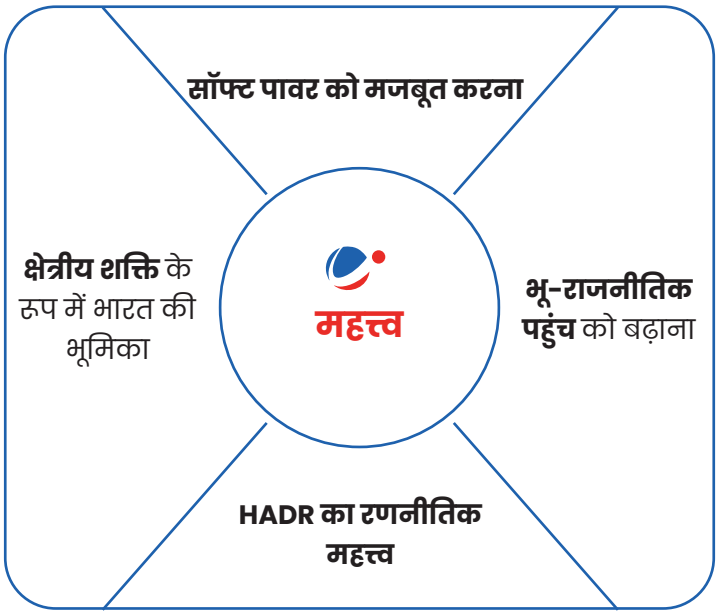

1.4. पैरा-डिप्लोमेसी

यह गैर-केंद्रीय सरकारों की विदेश नीति क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में केंद्र सरकार से स्वतंत्र उनकी भागीदारी को इंगित करती है।

प्रमुख तथ्य

- विदेशी मामले विशेष रूप से **"संघ" का विषय है**
- **सिस्टर-सिटी:** मुंबई और हो ची मिन्ह सिटी, (वियतनाम); चेन्नई और ग्वांगझोउ सिटी(चीन)।
- **उभरती प्रवृत्तियां:** बॉर्डर हाट; विदेशी सहयोग

पैराडिप्लोमेसी का महत्त्व

- **उप-राष्ट्रीय सरकार** के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ावा देता है।
- स्थानीयता के **वैश्वीकरण को सुगम** बनाता है।
- **शहरों** का वैश्विक **महत्व** बढ़ता है।

चुनौतियां

- राज्यों की **सीमित वित्तीय भूमिका।**
- अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों की प्रभावी भागीदारी पर **डेटा या सिद्धांत का अभाव।**
- जब राज्य केंद्र से असामान्य व्यवहार करते हैं तो **विदेश नीति में समन्वय का अभाव** होता है।

निष्कर्ष

भारत में पैराडिप्लोमेसी अब भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। पैराडिप्लोमेसी की क्षमता का उपयोग करके, भारत अपनी विविध क्षेत्रीय शक्तियों का लाभ उठा सकता है।

1.5. भारत की सामरिक स्वायत्तता

परिभाषा: सामरिक स्वायत्तता का मतलब है महत्वपूर्ण नीतिगत क्षेत्रों में, विशेषकर बड़े शक्तिशाली देशों के दबाव से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने की क्षमता। दूसरे शब्दों में सामरिक स्वायत्तता किसी देश की वह क्षमता है जिसके तहत वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए, बिना किसी बाहरी दबाव में आकर, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बना सकता है और कार्यान्वित कर सकता है।

भारत की सामरिक स्वायत्तता के प्रमुख स्तंभ

- **बहु-दिशात्मक कूटनीति का अनुसरण**
- **विभिन्न मुद्दों के बीच तालमेल**
- **उलझन भरे गठबंधनों से बचाव**
- **व्यापार संबंधों में संतुलन**
- **ऊर्जा बास्केट का विविधीकरण**

समस्याएं

- भारत पर आरोप लगाते हैं कि वह **अस्पष्ट रुख** अपनाने वाला देश है।
- यूरोपीय शक्तियां भारत पर **युद्ध को परोक्ष तरीके से वित्त-पोषित** करने का आरोप लगाती हैं।
- **रूस-चीन-पाकिस्तान की धुरी** का उदय।

आगे की राह

- **भारत अमेरिका और चीन के विकल्प के रूप में उभर सकता है।**
- **आत्मनिर्भरता** या जोखिमों का विविधीकरण।
- **अंतर्राष्ट्रीयवाद** और **बहु-गठबंधन आधारित विदेश नीति** का पालन करना।

1.6. भारत: द वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ

भारत: ग्लोबल साउथ का नेतृत्वकर्ता

- **बहु-दिशात्मक कूटनीतिक** सहभागिताएं
- भारत वैश्विक स्तर पर **जलवायु गवर्नेंस के लोकतंत्रीकरण** की दिशा में अपना सहयोग दे रहा है
- बहुपक्षीय संस्थानों को अधिक समावेशी बनाने के लिए उनमें **सुधार का पुरजोर समर्थन** कर रहा है
- ग्लोबल साउथ की **क्षमता निर्माण** के लिए कार्य कर रहा है

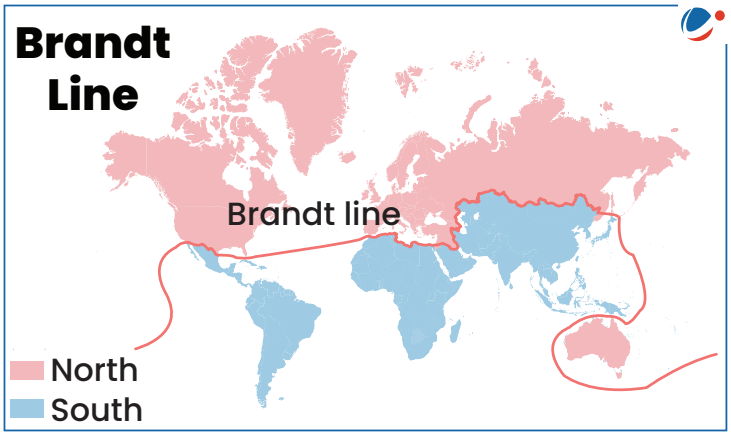

चुनौतियां

- वैश्विक मंचों पर **कम प्रतिनिधित्व**
- **ग्लोबल नॉर्थ के भू-राजनीतिक संघर्ष** दक्षिण को भी प्रभावित कर रहे हैं
- **वैश्विक चुनौतियों का** ग्लोबल साउथ पर **विषमतापूर्वक प्रभाव** पड़ता है

आगे की राह

भारत का 5 स्तंभ दृष्टिकोण: सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि

भारत ने 4R (रिस्पांस, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट और रिफ़ॉर्म) के वैश्विक एजेंडे **का आह्वान किया है**

1.7. भारत और विकासात्मक सहयोग

मुख्य तथ्य

- विकासशील देशों को 34.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की **रियायती क्रेडिट लाइंस**
- **सहायता अनुदान** से जुड़ी परियोजनाएं
- **97 देशों और संयुक्त राष्ट्र के दो संस्थाओं को कोविड टीकों** की 162.43 मिलियन खुराकें प्रदान की गईं
- **भारत के बजट का 1%** से भी कम

भारत के डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क (विकास सहयोग ढांचे) के 5 मुख्य तत्व

- **रियायती वित्त-पोषण**
- **प्रौद्योगिकी साझाकरण**
- **क्षमता निर्माण**
- **अनुदान**
- ऐसा व्यापार जिसमें भारतीय बाजार को **शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त पहुँच** उपलब्ध कराई जाती है

1.8. सॉफ्ट पॉवर और सांस्कृतिक कूटनीति

सॉफ्ट पावर गैर-आक्रामक साधनों का उपयोग करके अपील और आकर्षण के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है।

सांस्कृतिक कूटनीति "देशों और लोगों के बीच विचारों, सूचनाओं, कला, भाषा और संस्कृति के अन्य पहलुओं का आदान-प्रदान" है ताकि आपसी समझ को बढ़ावा दिया जा सके।

भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के साधन

- **योग:** संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी।
- **भारतीय सिनेमा:** दुनिया भर में इसके बहुत से दर्शक हैं।
- **भारतीय मूल्य और सहिष्णुता:** ये अपनी प्रकृति में काफी हद तक सकारात्मक माने जाते हैं।
- **भारतीय भोजन:** सांस्कृतिक विविधता के साथ-साथ भारत में कई तरह के आकर्षक व्यंजन मिलते हैं।
- **पर्यटन:** लोगों और संस्कृति को जोड़ने में मदद करता है।

1.9. भारतीय डायस्पोरा

डायस्पोरा भारत और विश्व को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेतु के रूप में कार्य करते हैं और उनमें से प्रत्येक देश का ब्रांड एंबेसडर होता है।

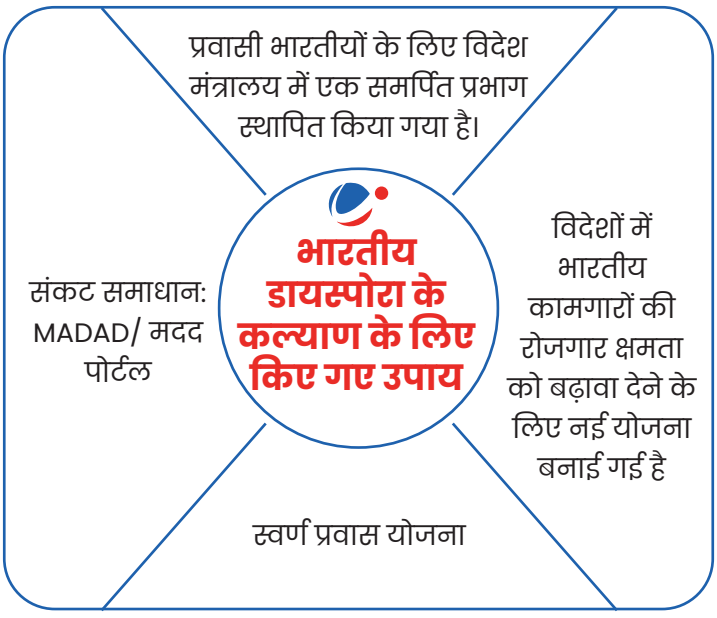

1.10. बंदरगाहों का भू-राजनीतिक महत्त्व

बंदरगाहों का सामरिक महत्त्व

- **भू-राजनीतिक परिसंपत्तियों** के रूप में कार्य करते हैं
- **समुद्री सुरक्षा** को मजबूत करते हैं
- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय **संबंधों को मजबूत** करते हैं
- **कनेक्टिविटी बढ़ाना** एवं व्यापार को सुविधाजनक बनाना एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखला में देश की भागीदारी को सक्षम बनाते हैं

हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक प्रतिस्पर्धा

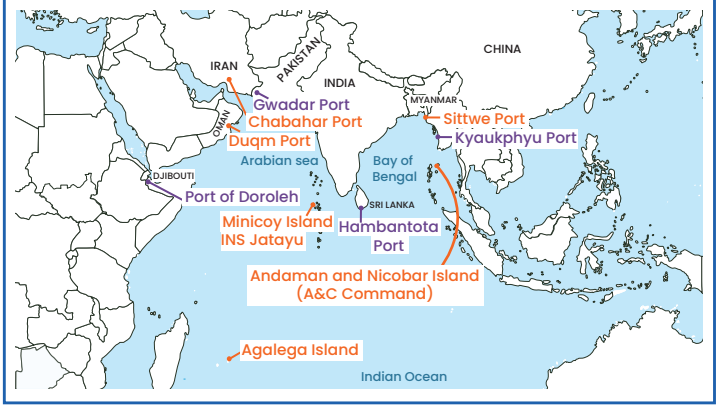

चुनौतियां

- **चीन की ऋण जाल कूटनीति** (हंबनटोटा के संबंध में)
- भारत के छोटे पड़ोसी देश (जैसे- श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव आदि) स्वयं को चीन और भारत की **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में फंसा हुआ** महसूस करते हैं
- **राष्ट्रों के बीच प्रतिद्वंद्विता:** उदाहरण के लिए- स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स (चीन) और नैकलेस ऑफ डायमंड्स (भारत)
- समुद्री डकैती के कारण **रक्षा एवं सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं**

1.11. सामरिक उपकरण के रूप में क्रूड ऑयल

क्रूड ऑयल के मामले में भारत की स्थिति

- **प्रमुख आपूर्तिकर्ता** देश हैं: रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात।
- भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तेल का **तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है।**
- वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की **मांग में होने वाली वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25-28%** रहने की संभावना है।
- भारत दुनिया का **चौथा सबसे बड़ा** क्रूड ऑयल **रिफाइनर** है।

कच्चे तेल का सामरिक महत्त्व

- **आर्थिक लाभ उठाने** के एक साधन के रूप में क्रूड ऑयल, उदाहरण के लिए- ओपेक
- क्रूड ऑयल आयात करने वाले देशों के साथ **रणनीतिक साझेदारी**
- **भू-राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन,** उदाहरण के लिए- तेल समृद्ध खाड़ी के देश।
- **प्रतिबंध के साधन** के रूप में

2. भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और समझौते (REGIONAL, AND GLOBAL GROUPINGS AND AGREEMENTS INVOLVING INDIA AND/OR AFFECTING INDIA'S INTEREST)

2.1. भारत और G20

भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में **"वसुधैव कुटुंबकम्" अथवा "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य"** की थीम के साथ किया गया

भारत के लिए G20 की अध्यक्षता का महत्त्व

- **नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन:** उदाहरण के लिए- ग्लोबल बायोफ्यूल अलायन्स (GBA)।
- **ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति:** भारत की पहल पर ही अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया।
- **आर्थिक अवसर:** उदाहरण के लिए, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)।
- **भारत के प्रभाव का विस्तार**

G20 का महत्त्व

- वैश्विक **वित्तीय स्थिरता** का समर्थन करना
- **वैश्विक विकास के समक्ष विद्यमान चुनौतियों** का समाधान करना
- **मानव संसाधन विकास** एवं रोजगार
- द्विपक्षीय संबंधों को **बेहतर बनाना**

G20 के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- सदस्य देशों के **अलग-अलग हित** और प्राथमिकताएं।
- G20 **संस्था और इसके समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।**
- G20 के कई सदस्य देशों के बीच **भू-राजनीतिक तनाव** हैं।
- **वैश्विक चुनौतियों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया।**

2.2. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा

MEC में **रेलमार्ग, जहाज-रेल पारगमन नेटवर्क (सड़क और समुद्र) तथा सड़क परिवहन मार्ग (व नेटवर्क)** शामिल होंगे। **इसमें दो गलियारे शामिल हैं:**

- **पूर्वी गलियारा:** यह **भारत को अरब की खाड़ी** से जोड़ेगा।
- **उत्तरी गलियारा:** यह **अरब की खाड़ी को यूरोप** से जोड़ेगा।

महत्त्व

- अमेरिका, यूरोप तथा भारत के बीच **प्रतिबद्धता की स्थापना।**
- **व्यापार सुविधा** से व्यापार लागत कम हो जाएगी आदि।
- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी** में वृद्धि
- यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच **आर्थिक एकीकरण** में प्रभावी भूमिका निभाएगा
- सुरक्षित **क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना**
- **भारत के लिए IMEC का महत्त्व:** इससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में लगभग 40 फीसदी तक की वृद्धि होने की संभावना है; इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी

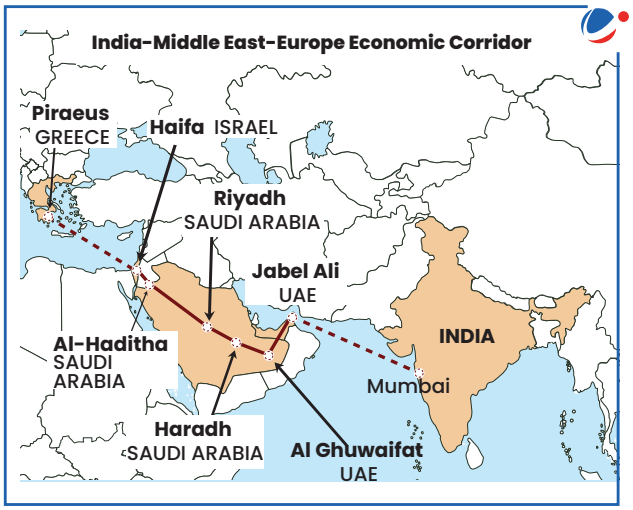

2.3. अफ्रीकी संघ: G20 का एक स्थायी सदस्य

अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का महत्त्व

G20 के लिए महत्त्व
अफ्रीका में **विश्व के 60% नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन** मौजूद हैं।

भारत के लिए महत्त्व
ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति बनना
भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप
संसाधनों का विविधीकरण

अफ्रीका के लिए महत्त्व
वैश्विक मुद्दों के लिए एक मंच
अफ्रीका की संवृद्धि का संकेत

अफ्रीकी संघ (AU) के बारे में

AU के बारे में: यह एक महाद्वीपीय संगठन है। अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश इस संघ के सदस्य हैं।

उत्पत्ति: इसे 2002 में स्थापित किया गया था।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी: इस समूह के सदस्य देशों की कुल आबादी 1.4 अरब और GDP 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

अफ्रीकी महाद्वीप के साथ एकीकरण को बढ़ावा देने में भारत के प्रयास

- **पैन अफ्रीकन ई-नेटवर्क प्रोजेक्ट (PANEP)**
- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम**
- **एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा:** भारत व जापान के सहयोग से
- **भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन:** भारत और अफ्रीका के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना

2.4. ब्रिक्स का विस्तार

मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पूर्णकालिक स्थायी सदस्यों के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं।

ब्रिक्स के विस्तार का महत्त्व

- नए क्षेत्रों में **ब्रिक्स समूह के फुटप्रिंट** का विस्तार करने में
- वैश्विक अर्थव्यवस्था में **प्रभाव बढ़ना**
- **वि-डॉलरीकरण** को बढ़ावा देने में
- **बहुध्रुवीय विश्व** को आकार देने में

भारत के लिए ब्रिक्स का महत्त्व

- प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन करने के लिए **तटस्थ मंच** प्रदान करता है
- वैश्विक संस्थाओं में **सुधार हेतु दबाव** डालने की अनुमति देता है।
- आयात स्रोतों के **विविधीकरण में मदद** करता है
- SDGs को **हासिल करने में ब्रिक्स** सहयोग (जैसे- कृषि अनुसंधान मंच) भारत के लिए काफी मददगार हो सकता है
- वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए UNSC और WTO जैसे संस्थानों में **सुधारों पर जोर देना**

ब्रिक्स के विस्तार से संबंधित मुद्दे

- ब्रिक्स समूह में शामिल किए गए देशों के **आर्थिक विकास का स्तर काफी अलग-अलग है।**
- **चीन** इस संगठन के द्वारा अपने **प्रभाव** क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
- सदस्यों के बीच व्यापक **आंतरिक मतभेद।**

2.5. भारत और हिंद-प्रशांत

हिंद-प्रशांत एक ऐसा क्षेत्र है जो अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर अमेरिका के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है।

महत्त्व

- **वैश्विक व्यापार का 50% और तेल का 40% हिस्सा** हिंद-प्रशांत क्षेत्र से गुजरता है।
- **भारत का 90 प्रतिशत व्यापार** इस क्षेत्र से होता है। इसमें 80 प्रतिशत महत्वपूर्ण माल ढुलाई शामिल हैं।
- एक **स्वतंत्र, खुले और समावेशी** क्षेत्र के समर्थक।
- **दक्षिण पूर्व एशिया और आसियान** को IP के केंद्र में रखता है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की नीति

- **समुद्री डोमेन जागरूकता** (MDA)
- **पहल:** IPOI, IONS
- **सुरक्षा प्रदाता** एवं प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता
- **विदेश नीति:** इंडो-पैसिफिक डिवीजन (IPD), एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर आदि।

चुनौतियां

- **सीमित नौसैनिक क्षमता** और सैन्य ठिकानों की कमी।
- विभिन्न पहलों के विकास की धीमी गति।
- हिंद-प्रशांत की निश्चित सहमति का अभाव।

2.6. इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF)

IPEF के बारे में

उत्पत्ति: इसे मई 2022 में **टोक्यो** में लॉन्च किया गया था। इसे **संयुक्त राज्य अमेरिका और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार** देशों ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था।

सदस्य: IPEF के **14 भागीदार** देश है। इनमें भारत भी शामिल है।

IPEF के भागीदार देशों की **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 40% और वैश्विक वस्तु एवं सेवा व्यापार में 28% की हिस्सेदारी** है।

पारंपरिक व्यापार समझौते बनाम IPEF

- पारंपरिक व्यापार समझौतों या मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के विपरीत, IPEF के तहत प्रशुल्क या बाजार पहुंच पर वार्ता नहीं की जाएगी।
- FTA में हर विषय पर एक ही तंत्र के अधीन चर्चा की जाती है। इसके विपरीत, **IPEF के तहत वार्ताएं चार मॉड्यूल (स्तंभों) के अधीन एक-दूसरे से स्वतंत्र व अलग** होती हैं।
- IPEF के अंतर्गत देशों को **प्रत्येक मॉड्यूल में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं** होती है।

आर्थिक फ्रेमवर्क के चार स्तंभ

जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था (व्यापार): डिजिटल अर्थव्यवस्था में उच्च मानकों को अपनाना, जिसमें सीमा-पार डेटा प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण से संबंधित मानक शामिल हों।

मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था (आपूर्ति श्रृंखला): अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत और लचीला बनाने हेतु ऐसी आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास करना होगा, जिस पर अचानक पड़ने वाले किसी आघात व महंगाई का असर न हो।

पारदर्शी अर्थव्यवस्था: स्वच्छ ऊर्जा, विकार्बनीकरण और अच्छे वेतन वाली नौकरियों को बढ़ावा देने वाली अवसंरचना को प्रोत्साहित करना।

निष्पक्ष अर्थव्यवस्था: मौजूदा बहुपक्षीय दायित्वों के अनुरूप प्रभावी कर व्यवस्था तथा मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी और रिश्वत विरोधी व्यवस्थाओं को अपनाना व उन्हें लागू करना।

2.7. क्वाड

भारत के लिए क्वाड (QUAD) का महत्त्व

हिंद-प्रशांत क्षेत्र दुनिया की सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है।

एक्ट ईस्ट को बढ़ावा

क्वाड भारत को **निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान** बना सकता है

क्वाड के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **पूरी तरह से संस्थागत नहीं**
- **शीत-युद्ध की मानसिकता**
- **क्वाड के उद्देश्य को अन्य क्षेत्रीय समूहों से अलग परिभाषित करना**
- **अपने प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ावा देने में असमर्थता**

क्वाड संबंधी भारत की चिंताएं

- **विभिन्न मोर्चों पर चीन के साथ फिर से तनाव होने की संभावना**
- भारत ने ऐसे देशों या संगठनों के साथ भी **साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखा है, जो तथाकथित क्वाड विरोधी हैं**
- क्वाड में भारत की भागीदारी बढ़ने से अन्य महत्त्वपूर्ण भागीदार, जैसे- **रूस और ईरान भारत से दूर हो सकते हैं।**

आगे की राह

- **क्षेत्रीय समृद्धि** पर ध्यान देना
- **स्पष्टता और अस्पष्टता को संतुलित करना**
- क्षेत्र में **मौजूदा संगठनों को बढ़ाना**
- **अन्य भागीदारों को शामिल** करना

2.8. भारत-आसियान संबंध

प्रमुख डेटा

- **आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।**
- **भारत-आसियान व्यापार: 122.67 बिलियन डॉलर (2023-24)**
- **भारत के वैश्विक व्यापार में** आसियान के साथ किए गए व्यापार का **हिस्सा 11.3 प्रतिशत था**
- **भारत के बाहरी निवेश का 20% से अधिक आसियान देशों को जाता है**

भारत के लिए आसियान का महत्त्व

- **भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक विज़न में** आसियान का केंद्रीय स्थान है
- भारत-म्यांमार-थाईलैंड **(IMT)** त्रिपक्षीय राजमार्ग; **कलादान मल्टीमॉडल परियोजना**
- आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस **(ADMM-Plus)**, आसियान-भारत समुद्री सैन्य अभ्यास **(AIME)**

चुनौतियाँ

- RCEP से **भारत का बाहर होना, म्यांमार का मुद्दा**
- **आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है**
- **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का मुख्य केंद्र बन गया है**
- **आसियान देशों के साथ चीन का समुद्री विवाद**

आगे की राह

- समयबद्ध तरीके से **AITIGA की समीक्षा** करना
- ISA, CDRI, LiFE और OSOWOG को **संस्थागत बनाना**
- **व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना:** IPOI, AOIP
- IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना को तेजी से पूरा करना

2.9. राष्ट्रमंडल

राष्ट्रमंडल के साथ भारत के संबंध

- भारत **राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा सदस्य देश** है
- भारत राष्ट्रमंडल में **चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता** देश है
- भारत ने **नई दिल्ली** में **1983 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन (CHOGM)** और 2010 में **राष्ट्रमंडल खेलों** की मेजबानी की
- 2018 में **कॉमनवेल्थ सब-विंडो** की स्थापना की गई

पक्ष में तर्क

- 1967 से अब तक राष्ट्रमंडल ने **लगभग 40 देशों में** चुनावों की निगरानी हेतु **140 मिशन** भेजे हैं।
- **टोगो और गैबॉन** (ये दोनों ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं थे) जैसे नए सदस्यों का शामिल होना।
- राष्ट्रमंडल **SDGs को लागू करने,** के प्रति प्रतिबद्ध है।

विपक्ष में तर्क

- इसका **अस्तित्व ही उपनिवेशवाद को वैधता प्रदान** करता है।
- समकालीन वैश्विक मुद्दों का समाधान करने में **कम प्रासंगिक** है।
- सदस्यों के बीच **सामंजस्य का अभाव।**
- **फंडिंग/ डिलीवरी** संबंधी रुकावट/ बाधाएं।

2.10. गुटनिरपेक्ष आंदोलन

NAM के बारे में

- इसकी उत्पत्ति 1955 में बांडुंग (इंडोनेशिया) में आयोजित **एशिया-अफ्रीका सम्मेलन** से मानी जाती है।
- **संस्थापक:** मिस्र, घाना, भारत, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया के राष्ट्राध्यक्ष।
- इन देशों का विचार था कि **स्वयं को "गुटनिरपेक्ष" घोषित किया जाए**
- 1961 में NAM का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पास **कोई औपचारिक संस्थापक चार्टर या संधि नहीं है। साथ ही, इसका कोई स्थायी सचिवालय भी नहीं** है।

वर्तमान समय में NAM की प्रासंगिकता

- **NAM देश आत्मनिर्णय के सिद्धांतों** का समर्थन करते हैं।
- **बहुपक्षवाद** और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने का समर्थन करता है।
- **उपनिवेशीकरण** को रोकने के लिए एक सख्त उपाय के रूप में यह अभी भी लागू है।
- **सक्रिय गुटनिरपेक्षता** की अवधारणा का बढ़ता महत्व।

चुनौतियां

- **वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन**
- **विकासशील गठबंधन**
- **आसियान और SCO जैसे क्षेत्रीय संगठन**
- **नेतृत्व का अभाव**

3. भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध (INDIA AND ITS NEIGHBOURHOOD RELATIONS)

3.1. भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी

महत्त्व

- चीन का मुकाबला करने के लिए **दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना।**
- **भारत, ग्लोबल साउथ की एक आवाज़**
- **बहुपक्षवाद को मजबूत करना**
- **सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए** भारत के सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाना
- **क्षेत्रीय व्यापार और निवेश** को बढ़ावा मिलेगा

चुनौतियां

- **ऐतिहासिक और अनसुलझे विवाद**
- **बिग-ब्रदर' अवधारणा**
- **भारत की घरेलू राजनीति:** भारत की श्रीलंका के प्रति विदेश नीति का निर्धारण।
- **पड़ोसी देशों में गतिशीलता या राजनीतिक अस्थिरता**
- **बनिष्क्रिय क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्थान;** जैसे, सार्क।

मुख्य सिफारिशें

- विदेश मंत्रालय को कार्यान्वित की जाने वाली विशिष्ट पहलों, परियोजनाओं की पहचान करने के लिए **एक सेल की स्थापना** करनी चाहिए।
- **वैध प्रवासन का समाधान करना।**
- **सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क** को बढ़ावा देना चाहिए।
- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय/क्षेत्रीय फ्रेमवर्क्स की **आवधिक समीक्षा करनी चाहिए।**

3.2. चीन का उदय और भारत के लिए खतरा

भारत के लिए चीन के प्रमुख सामरिक खतरे

- **लद्दाख में चीनी घुसपैठ**
- **चीन का रक्षा बजट 222 बिलियन डॉलर है, जबकि भारत का 75 बिलियन डॉलर।**
- **चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 99 बिलियन डॉलर से अधिक है।**
- **चीन अपने आर्थिक प्रभुत्व का उपयोग जियो-पोलिटिकल लाभों के लिए कर रहा है (जिसे "जिओ-इकोनॉमिक्स" कहा जाता है।**

इन खतरों को कम करने के लिए भारत के प्रयास

- **चीनी सेना का डटकर सामना करना**
- **भारत की सक्रिय हिंद-प्रशांत नीति**
- **क्वाड बहुआयामी गठजोड़ में तब्दील हो गया**
- **चीनी आर्थिक प्रभुत्व को कम करने का प्रयास करना-** उदाहरण के लिए- टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाना।
- **भारत : ग्लोबल साउथ के एक पक्षकार के रूप में उभर रहा है**

3.3. भारत-चीन सीमा विवाद

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) दोनों देशों के बीच **विभाजन रेखा** है। हालांकि, भारत और चीन के बीच सीमा का **औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं किया** गया है। दोनों देशों के बीच **पारस्परिक रूप से सहमति आधारित LAC** भी नहीं है।

- **वेस्टर्न सेक्टर (लद्दाख): भारत 1865** में निर्धारित **जॉनसन लाइन** को सीमा मानता है। वहीं चीन **1893 में निर्धारित मैकडॉनल्ड लाइन को वास्तविक सीमा** मानता है।
- **मिडिल सेक्टर (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड):** इस सेक्टर में मामूली विवाद है।
- **ईस्टर्न सेक्टर (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम):** चीन यह दावा करता है कि **अरुणाचल प्रदेश तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है।**

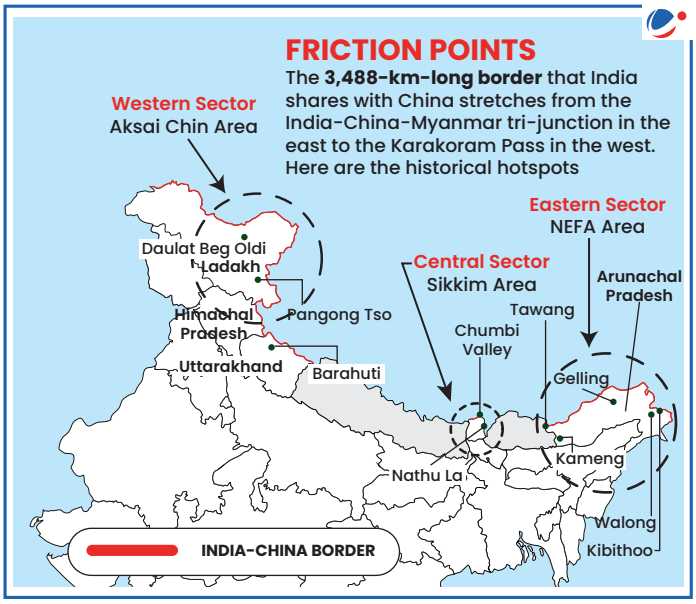

दोनों देशों के बीच प्रमुख विवाद समाधान पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **1993:** LAC पर शांति और स्थिरता के रखरखाव पर **समझौता।**
- **1996:** LAC पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास-निर्माण उपायों पर **समझौता।**
- **2005:** सैन्य क्षेत्र में विश्वास-निर्माण उपायों के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर **प्रोटोकॉल।**
- **2012:** भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्यकारी तंत्र की स्थापना पर **समझौता।**
- **2013: सीमा रक्षा सहयोग समझौता।**

3.4. सीमापारीय नदी जल प्रबंधन

परिभाषा: इसे प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों में बाह्य दबाव से स्वतंत्र रहकर निर्णय लेने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें विशेष रूप से महाशक्तियों के दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेना शामिल है।

प्रमुख मुद्दे

- **चीन तिब्बत पर अपने पूर्ण नियंत्रण** के परिणामस्वरूप जल आधिक्य (Water hegemony) की स्थिति में है।
- एक **सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था** की अनुपस्थिति
- प्रस्तावित **तीस्ता समझौते** का पश्चिम बंगाल द्वारा विरोध
- नदियों के कारण **सीमा विवाद**
- **डेटा साझाकरण का अभाव**

भारत और पड़ोसी देशों के बीच नदी जल सहयोग

- **1960:** सिंधु जल संधि
- **1996:** भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी जल के बंटवारे पर संधि
- **1954:** कोसी नदी समझौता
- **1959:** गंडक नदी समझौता
- **1991:** टनकपुर बैराज समझौता
- **1996:** महाकाली नदी संधि

3.5. भारत-नेपाल संबंध

भारत और नेपाल के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने और बहुत मजबूत हैं तथा दोनों देशों को इन संबंधों को और अधिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए काम करना चाहिए -भारतीय प्रधान मंत्री

प्रमुख तथ्य

- भारत नेपाल का **सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार**
- **द्विपक्षीय व्यापार:** दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार **11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक** का है।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाएं:** रक्सौल-काठमांडू रेलवे परियोजना, BBIN (बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया) आदि।
- **रोटी-बेटी का संबंध**

चुनौतियां

- **नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव**
- सीमा विवाद पर **नेपाल का आक्रामक रुख** (कालापानी सीमा मुद्दा)।
- **नेपाल में द्विपक्षीय व्यापार में भारी व्यापार घाटे के कारण असंतोष व्याप्त** है। यह घाटा GDP का लगभग 18 प्रतिशत है।
- **भारत का बड़े भाई के जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया जाता है।**
- **लोगों की अप्रतिबंधित सीमा पार आवाजाही**

संबंधों को बेहतर बनाने हेतु उठाए जाने वाले कदम

- **आर्थिक सहयोग** को मजबूत करना
- **मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी** पर ध्यान केंद्रित करना
- **विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा के लिए उपयुक्त** द्विपक्षीय तंत्र स्थापित करना
- **लोगों के मध्य संपर्कों** का लाभ उठाना
- **वर्ष 1950 की शांति और मित्रता संधि पर** फिर से विचार करना

3.6. भारत-भूटान संबंध

भारत के प्रधान मंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, **'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो'** से सम्मानित किया गया।

भूटान का महत्त्व

- चीन और भारत के बीच **भूटान की रणनीतिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण** है
- भूटान में **जल विद्युत संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध** हैं। ये संसाधन भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं।
- दोनों देश **पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन** के प्रति अनुकूलन पर एक साथ कार्य कर सकते हैं
- **क्षेत्रीय एकीकरण: जैसे-** सार्क (SAARC) और बिम्सटेक (BIMSTEC)

चुनौतियां

- **भारत पुनात्सांगछू-I और पुनात्सांगछू-II** जैसी परियोजनाओं को पूरा करने **देरी कर रहा है।**
- **उग्रवादियों/ विद्रोहियों के लिए छुपने का स्थान:** उदा. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोस (NDFB) आदि।
- **बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता :** पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण भूटान ने **इस समझौते को** रोक दिया है

आगे की राह

- **भारत को** भूटान के सेवा क्षेत्रक में **निवेश करने की आवश्यकता है।**
- सीमा विवादों के संबंध में बढ़ रही अनिश्चितताओं को कम करने के लिए **चीन के साथ ट्राइलोग (Trilogue/ त्रिपक्षीय बातचीत) की शुरुआत** की जानी चाहिए।
- **दोनों देशों के बीच संपर्क बिंदु (Contact points) स्थापित करना।** जानकारी को **रियल टाइम पर साझा** करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना आदि।

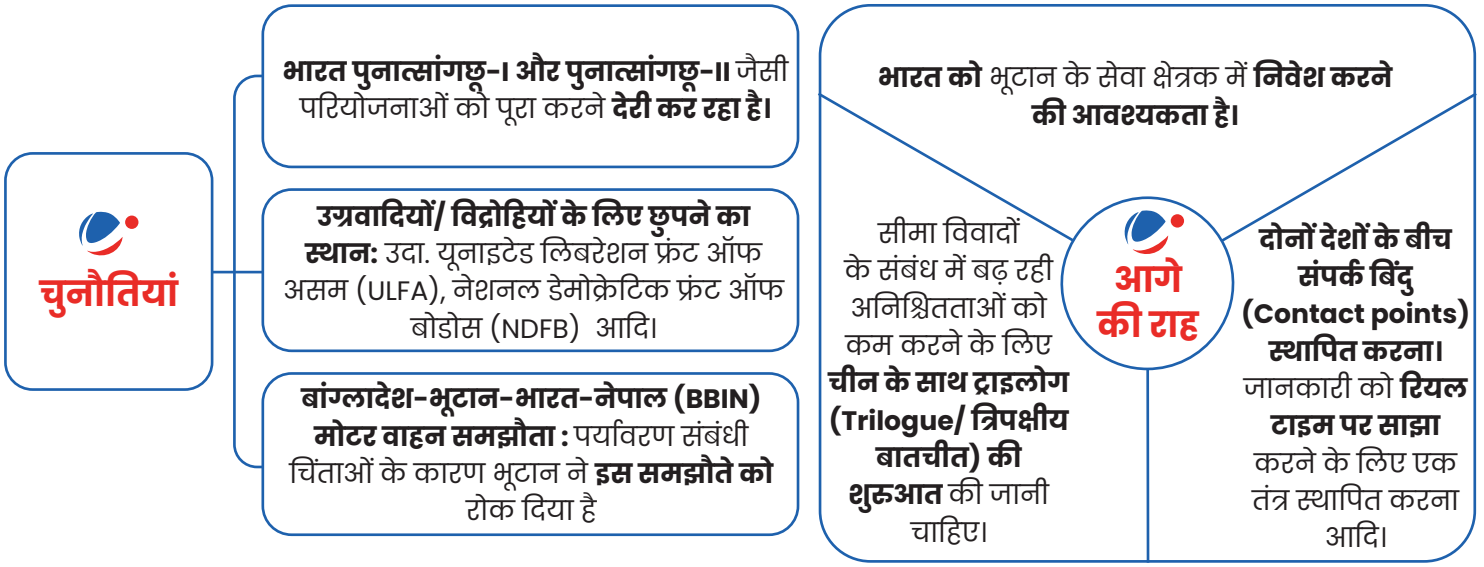

3.7. तालिबान शासन के तहत भारत-अफगानिस्तान संबंध

अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का भारत के लिए महत्त्व

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी
अफगानिस्तान को भारत के लिए **मध्य एशियाई क्षेत्र का प्रवेश द्वार** माना जाता है।

ऊर्जा और संसाधन
अफगानिस्तान में स्थिरता रहने से **"तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइन"** परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकता है।

सुरक्षा
पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए अफगानिस्तान में शांति बहाली आवश्यक है।

चुनौतियां

तालिबान की चरमपंथी धार्मिक विचारधारा

महिलाओं के अधिकार तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुंच

पाकिस्तान, **अफगानिस्तान** के किसी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किए बिना वहां अपना **सामरिक प्रभाव बढ़ाने** का प्रयास कर रहा है

दिल्ली में अफगान दूतावास को बंद कर दिया गया है

अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद से भारत-अफगान संबंध

- **काबुल में तकनीकी मिशन:** इसे जून 2022 में खोला गया था।
- भारत ने **अफगान छात्रों के लिए "भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) छात्रवृत्ति योजना"** जारी रखी है
- अमेरिका और अन्य अधिकांश देशों की तरह भारत ने भी तालिबान **सरकार को अभी तक मान्यता नहीं दी है।**
- भारत ने **"अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान द्वारा नियंत्रित** शांति प्रक्रिया के महत्त्व पर जोर दिया है।

आगे की राह

तालिबान से द्विपक्षीय वार्ता करने के साथ-साथ सार्क जैसे क्षेत्रीय मंचों पर भी उसके साथ चर्चा बढ़ानी चाहिए

भारत को अफगान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति समेत अन्य सुविधाएं देना जारी रखना चाहिए। साथ ही, **अफगान लोगों में भारत के प्रति मजबूत सद्भावना का लाभ भी उठाना** चाहिए।

3.8. भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित पड़ोसी देश

बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल के साथ-साथ जापान और आसियान के सदस्य भारत के सबसे भरोसेमंद वैश्विक भागीदार हैं।

प्रमुख मुद्दे/चिंता के विषय

- **खराब सीमावर्ती-अवसंरचना एवं खुली सीमाएँ (बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार)।**
- **डेथ ट्राइएंगल (थाईलैंड, लाओस और म्यांमार) के नारकोटिक्स वेब से निकटता।**
- **पूर्वोत्तर में शरणार्थी संकट: उदाहरण के लिए- रोहिंग्या संकट (म्यांमार), बांग्लादेश के अवैध प्रवासी।**
- **परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी।**

महत्त्व

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में विकास

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा:** जैसे- मादक पदार्थों की तस्करी,
- **भारत के प्रभाव क्षेत्र को सुरक्षित रखना और बनाए रखना**
- **क्षेत्र में मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक पकड़**
- **कनेक्टिविटी में सुधार: जैसे- 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'**
- **क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण**

आगे की राह

- **व्यापारिक और आर्थिक संबंधों** को आगे बढ़ाना।
- **सहयोग के नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना:** जैसे- डिजिटल प्रौद्योगिकी।
- **सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाना:** जैसे भारत का **बौद्ध सर्किट"**
- **सामरिक सहयोग: जैसे समुद्री क्षेत्र** में।
- **अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और मानदंडों के सृजन को बढ़ावा देना।**
- **सामरिक सहयोग:** विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र

3.9. भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा रेखा

इस समस्या के तीन परस्पर जुड़े हुए पहलू हैं: कच्चातिवू द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच असहमति; श्रीलंकाई जलक्षेत्र में भारतीय मछुआरों द्वारा अवैध मत्स्यन; तथा मछली पकड़ने में उपयोग होने वाले बड़े ट्रॉलर्स (जिनसे पर्यावरण को हानि पहुंचती है)।

कच्चातिवू और वेज बैंक के बारे में

- इसका निर्माण 14वीं सदी के **ज्वालामुखी उद्गार** से हुआ था।
- कच्चातिवू श्रीलंका की समुद्री सीमा रेखा के भीतर समुद्र में **285 एकड़ का एक क्षेत्र है।**
- **यह रामेश्वरम के उत्तर-पूर्व और श्रीलंका के डेल्फ़्ट द्वीप** के दक्षिण-पश्चिम में अवस्थित है।
- **वेज बैंक विश्व में मछली पकड़ने के सबसे समृद्ध जलीय क्षेत्रों में से एक है।**

3.10. भारत-मालदीव संबंध

मालदीव ने कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव वार्षिक बैठक (2023) से बाहर होने का विकल्प चुना तथा मालदीव ने चीन के साथ सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए।

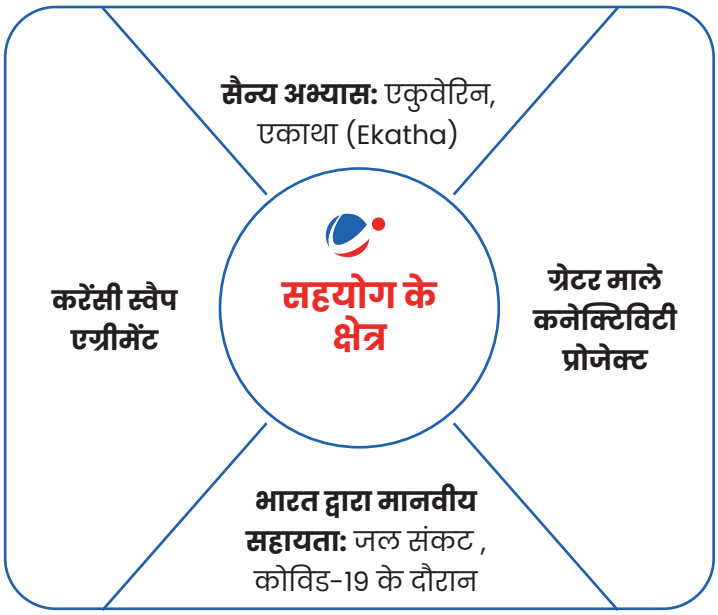

भारत के लिए मालदीव का महत्त्व

- **भू-सामरिक:** 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति
- **चीन के प्रभाव को संतुलित करना**
- **निवल सुरक्षा प्रदाता** की भूमिका
- **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग:** SAARC, IORA

आगे की राह

- सभी स्तरों पर खुला और पारदर्शी संचार
- सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना
- मुक्त व्यापार समझौते के विकल्प को तलाशना

3.11. दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC)

भारत के लिए SASEC का महत्त्व

- **दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया** के बीच कनेक्टिविटी
- **वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति** को मजबूत करेगी
- **चीन के OBOR का विकल्प**

SASEC के समक्ष चुनौतियां

- **प्रभावी सीमा-पार परिवहन अवसंरचना** की कमी
- पुरानी **सीमा प्रक्रिया**
- दक्षिण एशिया में **अंतर-क्षेत्रीय व्यापार संभावना का कम उपयोग** किया गया है

SASEC के चार स्तंभ

- SASEC परिवहन क्षेत्रक रणनीति
- SASEC व्यापार सुविधा
- SASEC ऊर्जा क्षेत्रक रणनीति
- SASEC आर्थिक गलियारा विकास रणनीति

आगे की राह

- सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देंना
- क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग
- क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत बनाना

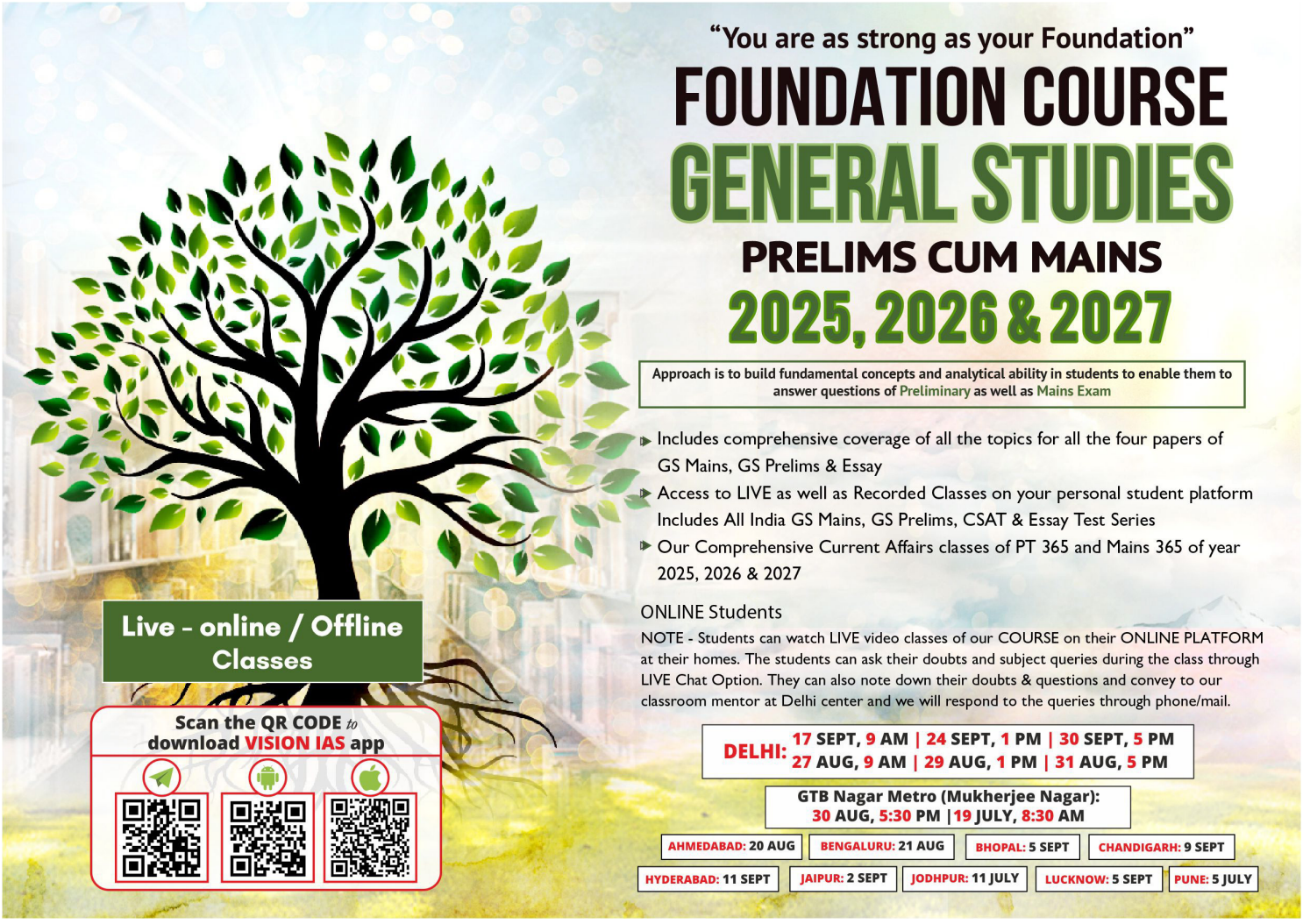

4. भारत को शामिल करने वाले और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समूह तथा समझौते (Bilateral Grouping and Agreements Involving India and/or Affecting India)

4.1. अब्राहम समझौता

अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर के 3 साल पूरे हुए। अब्राहम समझौता **संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और इज़रायल** के बीच एक सामूहिक समझौता है।

अब्राहम समझौते का महत्त्व

- सामूहिक सुरक्षा फ्रेमवर्क **द्वारा क्षेत्र में स्थिरता।**
- **इज़रायल-फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान**
- **प्रौद्योगिकी में सहयोग:** 'प्रॉस्पेरिटी ग्रीन एंड ब्लू एग्रीमेंट' किया गया

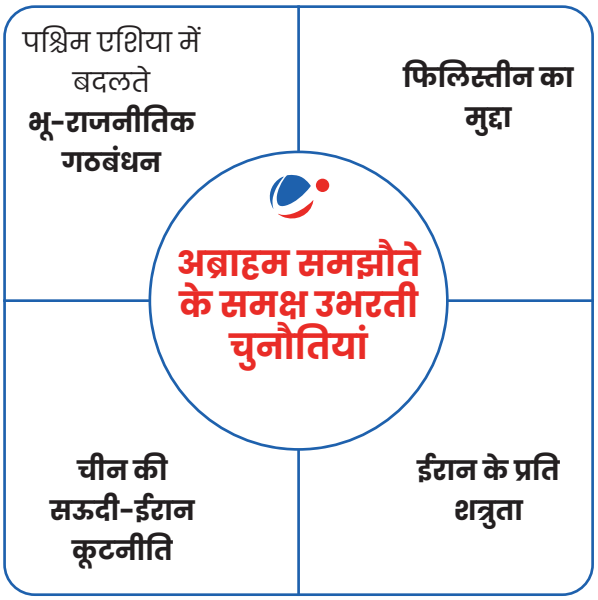

4.2. इज़रायल-फ़िलिस्तीन युद्ध

पश्चिम एशिया में अस्थिरता के प्रभाव

भारत पर

- **भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक संतुलन** का परीक्षण
- **समुद्री सुरक्षा** से जुड़ी चुनौतियां (लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले)
- **ऊर्जा सुरक्षा** के समक्ष खतरा एवं मध्य-पूर्व क्षेत्र में **प्रवासी भारतीयों** की सुरक्षा की चिंता
- **शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम** में वृद्धि

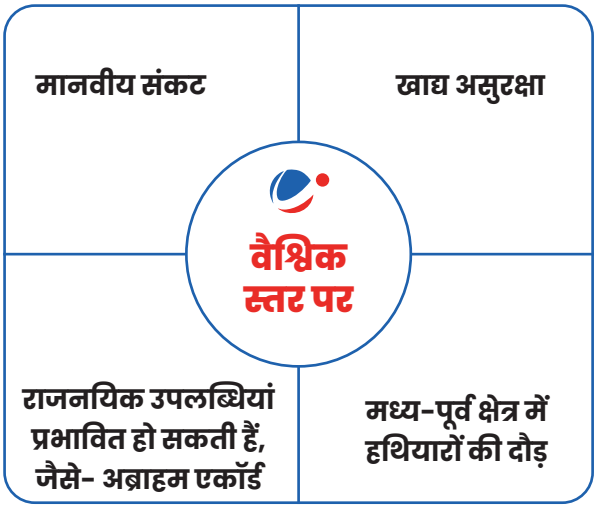

आगे की राह

तुरंत लागू किए जाने वाले उपाय: तत्काल और स्थायी युद्धविराम; **सभी बंधकों की** तत्काल और बिना शर्त रिहाई।

दीर्घकालिक उपाय: "व्यापक विनाश के हथियार मुक्त क्षेत्र" की घोषणा; **द्वि-राष्ट्र सिद्धांत**।

4.3. भारत-इजराइल संबंध

"भारत-इज़रायल संबंध स्वर्ग में बने रिश्ते हैं, जो धरती पर निभाए जाते हैं"- इज़रायली प्रधान मंत्री

बेहतर होता भारत-इज़रायल संबंध

- **द्विपक्षीय: उदाहरण के लिए,** रणनीतिक साझेदारी।
- **रक्षा:** BARAK-8 मिसाइल फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS)।
- **कृषि और जल:** इज़राइल की ड्रिप सिंचाई तकनीक।
- **बहुपक्षीय:** I2U2 की स्थापना।

चुनौतियां

फिलिस्तीन का प्रश्न

इज़राइल के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों के कारण अरब देशों के साथ इसके संबंध प्रभावित हो सकते हैं

मानवाधिकारों का उल्लंघन

निष्कर्ष

भारत-इज़राइल संबंधों को एक मजबूत, गतिशील और रेजिलिएंट रणनीतिक साझेदारी के रूप में सुदृढ़ बनाने के लिए भू-राजनीतिक हितों व लोकतांत्रिक आदर्शों पर एक मत बनाने और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को समन्वित करने की आवश्यकता है

4.4. भारत-संयुक्त अरब अमीरात (UAE) संबंध

भारत के प्रधान मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की आधिकारिक यात्रा के दौरान एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर हस्ताक्षर किए। देशों ने 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए थे। CEPA का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्रक

फिनटेक सहयोग: UPI (भारत) और AANI (संयुक्त अरब अमीरात) को जोड़ने हेतु समझौते।

बहुपक्षीय सहयोग: ब्रिक्स, I2U2

डायस्पोरा: UAE की आबादी में प्रवासी भारतीयों की संख्या लगभग 35% है।

अंतरिक्ष सहयोग: ISRO और UAE अंतरिक्ष एजेंसी

चुनौतियां

क्षेत्र में स्थायी शांति का न होना

कफ़ाला प्रणाली के कारण **प्रवासी मज़दूरों के अधिकारों** का हनन

व्यापार और बाजार पहुंच में बाधाएं

निष्कर्ष

संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध भारत के लिए न केवल द्विपक्षीय रूप से बल्कि **भारत की विस्तारित पड़ोस नीति और पश्चिम की ओर देखो नीति** के लिए भी महत्वपूर्ण है।

4.5. भारत-सऊदी अरब संबंध

भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) की पहली शिखर सम्मेलन स्तर की बैठक आयोजित हुई, भारत अपना 18% से अधिक कच्चा तेल सऊदी अरब से आयात करता है।

भारत के लिए सऊदी अरब का महत्त्व

- **भू-सामरिक: 'लुक वेस्ट' नीति और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC)।**
- **भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** में तेजी लाने में दोनों देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- **भारतीय प्रवासी:** सऊदी अरब में 2.4 मिलियन से अधिक प्रवासी भारतीय कार्यरत हैं।

चुनौतियां

मध्य-पूर्व में चल रहे **क्षेत्रीय संघर्ष**

शोषणकारी कफाला व्यवस्था

सऊदी अरब का **पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध**

आगे की राह:

व्यापार और वाणिज्य, श्रम कल्याण, आतंकवाद विरोधी उपायों से परे द्विपक्षीय जुड़ाव

4.6. भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) संबंध

GCC वर्तमान में **भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार समूह** है। वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों पक्षों के बीच **184 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया गया था।

महत्त्व

- **GCC, एक संभावित निवेश स्रोत:** उदाहरण के लिए- सऊदी अरब (100 बिलियन डॉलर) और UAE (75 बिलियन डॉलर) भारत की अर्थव्यवस्था में भारी निवेश की योजना बना रहे हैं।
- **IOR में "समग्र सुरक्षा प्रदाता" के रूप में भारत की भूमिका के लिए GCC का सहयोग आवश्यक है।**
- **भारत का क्षेत्रीय भू-आर्थिक फोकस।**
- **ऊर्जा सुरक्षा हेतु भारत को अभी भी GCC की आवश्यक है।**

चुनौतियाँ

खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में **आर्थिक गिरावट**

पश्चिम एशियाई देशों के साथ **पाकिस्तान के मजबूत सैन्य संबंध** है

चीन का सऊदी-ईरान से नज़दीकी का प्रयास

आगे की राह

- आर्थिक संबंधों में विविधता लाना
- क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करना
- भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौते को सुगम बनाना

4.7. भारत और पांच मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs) के संबंध

समन्वय के क्षेत्र

कनेक्टिविटी: INSTC और अश्गाबात समझौता।

ऊर्जा: तुर्कमेनिस्तान के पास चौथा सबसे बड़ा गैस भंडार है।

CARs में **शांति और सुरक्षा** अफगानिस्तान में शांति से जुड़ी हुई है

चुनौतियां

व्यापार: लगभग 2 बिलियन डॉलर, जबकि चीन का व्यापार लगभग 100 बिलियन डॉलर है।

भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: रूस और चीन की मौजूदगी के कारण।

कमजोर कनेक्टिविटी

निष्कर्ष

हाल के वर्षों में भारत-मध्य एशिया संबंधों की रूपरेखा में अभूतपूर्व तरीके से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसमें बढ़ते जुड़ाव से एक्सपेंडेड नेबरहुड की भू-रणनीतिक गतिशीलता के प्रतिमानों में बदलाव लाने की क्षमता है।

4.8. भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता: **द लैंप ऑफ द ईस्ट** में लिखा है- **"एशिया के स्वर्ण युग में, कोरिया उसके दीपकों में से एक था"**

2023 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2015 में अपने संबंधों को **"विशेष सामरिक भागीदारी"** में अपग्रेड किया।

महत्त्व

- **दक्षिण कोरिया की नई सदर्न पॉलिसी (NSP)** वस्तुतः भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है।
- **'कोरिया प्लस' पहल** का उद्देश्य भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देना है।
- भारत ने उत्तर कोरिया के परमाणु प्रसार को रोकने के लिए **"वैंकूवर डायलॉग" का समर्थन** किया था।

चुनौतियां

विश्व की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, **वैश्विक राजनीति में एक ऑब्जर्वर के रूप में रहना; भारत का दक्षिण** कोरिया के साथ व्यापार घाटा उत्तर कोरिया का मुद्दा।

आगे की राह

- रक्षा उद्योग में सहयोग को मजबूत करना और समुद्री प्रक्षेत्र जागरूकता
- सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए द्विपक्षीय एजेंडे का विस्तार

4.9. भारत-इंडोनेशिया संबंध

2024 में, भारत और इंडोनेशिया अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की **75वीं वर्षगांठ** मना रहे हैं।

महत्त्व

साझा इतिहास और सांस्कृतिक मूल्य: रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कहानियां इंडोनेशियाई लोक कला और नाटकों का स्रोत हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए विज़न में समन्वय: भारत की **एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडोनेशिया के ग्लोबल मैरीटाइम फलक्रम विजन** में परस्पर समन्वय है।

नई व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2018)

चुनौतियां

व्यापार असंतुलन (भारत द्वारा पाम तेल के आयात के कारण)

चीन का प्रभुत्व

कनेक्टिविटी का अभाव

आगे की राह

- पर्यटन संबंधी कूटनीति
- व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) को गति देना
- रणनीतिक इंटरफेस को बढ़ावा देना: इंडोनेशिया ISA, CDRI से जुड़ सकता है

4.10. दक्षिण चीन सागर

दक्षिण चीन सागर का महत्त्व

समुद्री व्यापार: वैश्विक व्यापार का 60% से अधिक

प्राकृतिक भंडार: कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, कोरल लाइम

मछली पकड़ने का प्रमुख स्थान; नौवहन या नौसंचालन की स्वतंत्रता

चुनौतियां

चीन की आक्रामकता में वृद्धि

अत्यधिक मछली पकड़ना, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचना

सैन्य अभ्यास करना आदि।

आगे की राह

- इस क्षेत्र के लिए **कोड ऑफ कंडक्ट** तैयार करना
- **ट्रांस बाउंड्री मैरीटाइम** पीस पार्क (MPP) की स्थापना
- **समुद्री मार्ग की स्वतंत्रता** सुनिश्चित करना

4.11. भारत-अमेरिका संबंध

भारत-अमेरिका आपसी संबंधों के एक नए दौर में हैं जो न केवल दोनों देशों की नियति को आकार देगा, बल्कि दुनिया की नियति को भी एक नया आकार देगा। भरोसे पर आधारित हमारी आपसी साझेदारी इस नए दौर में एक सूर्य की तरह है जो चारों ओर सकारात्मकता फैलाएगी। (पी.एम., भारत)

सहयोग के क्षेत्र

बहुपक्षीय और साथ ही मिनीलैटरल सहयोग: संयुक्त राष्ट्र, G20, IMF, क्वाड, I2U2,	**रक्षा:** इंडिया-अमेरिका डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम (INDUS-X), LEMOA/लेमोआ, कॉमकासा, BECA
प्रौद्योगिकी में रणनीतिक सहयोग: iCET (महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल)	**वैश्विक चुनौतियों के लिए सहयोग:** भारत-अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी

चुनौतियां

- **वैश्विक संघर्षों पर अलग-अलग रुख:** जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध, इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध।
- **रूस पर रक्षा निर्भरता:** CAATSA प्रतिबंधों का डर।
- **गुटनिरपेक्षता** के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता।

आगे की राह

- **बहुपक्षवाद** को पुनर्जीवित करना और सुधारना
- **क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना,** उदाहरण के लिए- क्वाड, I2U2
- आपूर्ति श्रृंखलाओं का **विविधीकरण, विकेंद्रीकरण और लोकतंत्रीकरण।**

4.12. भारत-कनाडा संबंध

कनाडा ने खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का दावा किया है।

सहयोग के क्षेत्र

भारतीय प्रवासियों की जनसंख्या कनाडा की कुल आबादी के 3 प्रतिशत से अधिक है।	**कनाडा की हिंद-प्रशांत नीति, चीन को "विघटनकारी वैश्विक शक्ति"** के रूप में स्वीकार करती है। साथ ही, यह नीति साझा हितों को पूरा करने हेतु सहयोग के लिए **भारत** को **"प्रमुख भागीदार"** के रूप में रेखांकित करती है।

चुनौतियाँ

- कनाडा की **आप्रवासन (Immigration) प्रणाली**
- **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)** वर्ष 2010 से लंबित है।
- **भारत के घरेलू मामलों** में हस्तक्षेप

आगे की राह

- **2018 में स्थापित आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग की रूपरेखा के तहत** दोनों देशों को सहयोग करना चाहिए।
- **कूटनीति को बढ़ावा देना**
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** की जिम्मेदारी

4.13. भारत- लैटिन अमेरिका संबंध

भारत के कुल आयात का लगभग 3% हिस्सा LAC (लैटिन अमेरिका और कैरिबियन) से आता है और भारत के आयात स्रोतों में इसका स्थान 8वां है। द्विपक्षीय व्यापार: 2022 में लगभग 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

महत्त्व

- मर्कोसुर/ MERCOSUR के साथ अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA)
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग**
- **खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा**

चुनौतियाँ

- **कूटनीतिक स्तर पर पर्याप्त ध्यान न देना**
- इस क्षेत्र के लिए कोई **सीधी पोत-परिवहन सेवाएं** नहीं
- **भाषा संबंधी बाधाएं**

आगे की राह

- **व्यापार विविधीकरण** और प्रगति
- **सुरक्षा और रक्षा** उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना
- **समकालीन वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने** के लिए धारणाओं का पुनर्निर्धारण करना

निष्कर्ष:

भारत की वैश्विक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा में लैटिन अमेरिका की भूमिका बनी रहेगी। लेटिन अमेरिका व्यापार के लिए **गोल्डीलॉक्स ज़ोन** (अर्थात, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अत्यधिक विनियमित और प्रतिस्पर्धी बाजार तथा कम क्रय शक्ति वाले अफ्रीका के कम प्रतिस्पर्धी बाजार के मध्य एक आकर्षक स्थान) का भी हिस्सा होगा।

4.14. भारत-यूरोपीय संघ संबंध

2022-23 में दोनों के मध्य **द्विपक्षीय व्यापार 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का था।

महत्त्व

- EU, भारतीय निर्यात के लिए **दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है**
- **बहुपक्षवाद:** UN, WTO, G20
- **EU की इंडो-पैसिफिक रणनीति इस क्षेत्र में** भारत के लक्ष्यों के करीब है
- **स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु भागीदारी**

चुनौतियां

- **बाजार तक पहुंच:** गैर-प्रशुल्क बाधा
- रोपीय संघ मजबूत **IPR व्यवस्था** की मांग करता है
- यूरोपीय संघ ने **धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार आदि** के बारे में चिंता जताई है

उठाए जाने वाले कदम

- **FTA** को शीघ्र संपन्न करना
- **विदेश एवं सुरक्षा नीति** और व्यापार एवं आर्थिक उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना
- **इंडिया-EU कनेक्टिविटी** पार्टनरशिप
- **ब्रेक्जिट के बाद के परिदृश्य में उपलब्ध अवसरों का पूरा लाभ उठाना**

निष्कर्ष

भारत और यूरोपीय संघ को केवल व्यापार वाले नजरिए से आगे बढ़कर अपने महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक और रणनीतिक समानताओं को पहचानना चाहिए।

4.15. भारत-रूस संबंध

"भारत और रूस के बीच संबंधों में स्थिरता बनी हुई है, यही कारण है कि ये हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं।" (विदेश मंत्रालय)

भारत के लिए रूस का महत्त्व

- **चीन को संतुलित करना**
- UNSC और NSG जैसे **बहुपक्षीय मंचों पर रूस का समर्थन**
- **परमाणु ऊर्जा:** भारत में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP)
- **निवेश के अवसर:** जैसे रूस का सुदूर पूर्व क्षेत्र
- रक्षा उपकरणों या साधनों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

चुनौतियां

- **रूस और चीन के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी**
- **रूस की पाकिस्तान के साथ नजदीकी**
- **भारत के लिए कूटनीतिक दुविधा:** उदाहरण के लिए, अमेरिका और रूस के बीच संतुलन
- **रूस की आलोचना:** क्वाड, हिंद-प्रशांत का विचार

संबंधों को और बेहतर बनाये जाने हेतु उठाए जाने वाले कदम

- द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों का विस्तार और विविधीकरण
- **क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग:** यूरेशियाई क्षेत्र, आर्कटिक, अफगानिस्तान
- **लॉजिस्टिक्स लिंक पर फोकस:** उदाहरण के लिए, उत्तरी समुद्री मार्ग की संभावनाएं

4.16. भारत-फ्रांस संबंध

भारत-फ्रांस साझेदारी "सार्वभौमिक" है क्योंकि यह "समुद्र से अंतरिक्ष तक" और उससे भी आगे तक है।

सहयोग के क्षेत्र

- **भारत के रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण:** जैसे राफेल जेट इत्यादि।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** उदाहरण के लिए- तृष्णा और मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह आदि।
- **भू-रणनीतिक:** 2023 रोडमैप ने हिंद महासागर क्षेत्र से लेकर संपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र तक द्विपक्षीय सहयोग को व्यापक बनाया है।

निष्कर्ष

निर्णायक मध्य शक्तियों के रूप में, फ्रांस और भारत बहुपक्षीय मंचों पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाकर, एक अधिक संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देकर और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों को गहरा कर अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर सकते हैं।

4.17. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध

हाल ही में, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने हेतु महत्वाकांक्षी **'प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल (TSI)'** शुरू की है।

भारत-ब्रिटेन संबंधों का महत्त्व

- **आक्रामक चीन** को संतुलित करना
- ब्रिटेन में **भारतीय प्रवासी**
- **रक्षा उत्पादन में सहयोग** की संभावनाएं

चिंताएं

- **भारत विरोधी गतिविधियों** से निपटने में विफलता
- **डिएगो गार्सिया का मुद्दा:** भारत ने मॉरीशस का समर्थन किया
- **भारत की घरेलू राजनीति** में ब्रिटिश हस्तक्षेप, उदाहरण के लिए, कश्मीर का मुद्दा।

भारत-UK मुक्त व्यापार समझौते (FTA)

लाभ

सामाजिक सुरक्षा समझौते (या टोटलाईजेशन अग्रीमेंट्स) के लागू होने से वीजा प्रक्रिया अधिक किफायती हो जाएगी, श्रम प्रधान क्षेत्रकों को बढ़ावा मिलेगा; चीन को प्रतिसंतुलित करने में मदद मिलेगी।

चिंताएं

यूनाइटेड किंगडम IPRs को और मजबूत बनाने के लिए WTO के ट्रिप्स (TRIPS) समझौते से इतर अन्य उपायों को अपनाने की भी वकालत कर रहा है; उत्पत्ति के नियम (ROO) के नियमों में उदारता; भारत ने BIT के लिए नया मॉडल तैयार किया है।

निष्कर्ष

भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में विकसित वैश्विक व्यवस्था में अपने लिए एक नई भूमिका बनाना चाहता है। यू.के. ब्रेक्जिट के बाद अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करने की चाह रखता है। **यह भारत और यू.के., दोनों के लिए एक अनूठा क्षण है।**

4.18. भारत-इटली संबंध

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **भारत और इटली के बीच प्रवासन व आवाजाही समझौते** को मंजूरी प्रदान की है।

सहयोग के क्षेत्र

- इटली यूरोपीय संघ में भारत का **चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** है
- **2023 में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए**
- **2023 में** भारत और इटली के बीच संबंधों को **रणनीतिक साझेदारी** तक बढ़ाया
- चीन की **बेल्ट एंड रोड पहल** से हटने का इटली का निर्णय

निष्कर्ष

हिंद-प्रशांत (जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभाता है) और विस्तृत भूमध्य सागर (जहां इटली केंद्र में स्थित है और हिंद-प्रशांत की ओर एक सेतु के रूप में कार्य करता है) के बीच एक संबंध की पहचान की गई।

4.19. भारत नॉर्डिक संबंध

महत्त्व

- **ब्लू इकोनॉमी**
- **आर्कटिक परिषद** में सहयोग
- नॉर्डिक देशों के **सॉवरेन वेल्थ फंड**

चुनौतियां

- **नॉर्डिक देश आर्कटिक क्षेत्र में रूस की** आक्रामकता के खिलाफ हैं
- सदस्यों के **अलग-अलग हित**
- **व्यापार बाधाएं:** टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाएं

4.20. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध

इस जटिल विश्व में, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे समान विचारधारा वाले साझेदारों के बीच विश्वास ही है जो एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ-साथ नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुरक्षित करने में मदद कर रहा है। (विदेश मंत्रालय)

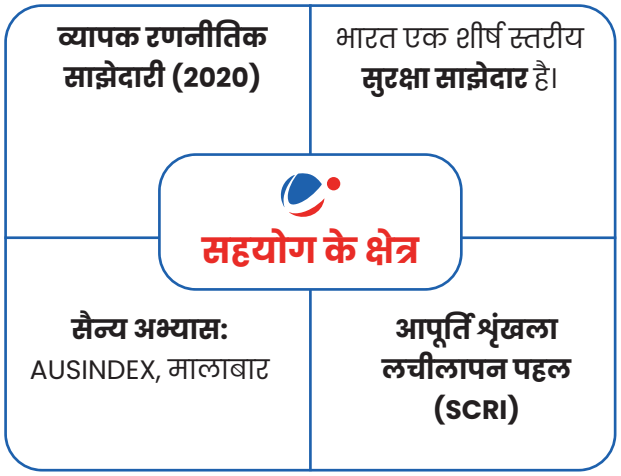

निष्कर्ष

भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख शक्तियाँ होने के कारण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक "कोएलिशन ऑफ मिडल पॉवर्स" के लिए उपयुक्त स्थिति में हैं।

4.21. भारत-अफ्रीका संबंध

"भारत की प्राथमिकता सिर्फ अफ्रीका नहीं है; भारत की प्राथमिकता सभी अफ्रीकी - अफ्रीका का हर पुरुष, महिला और बच्चा - हैं।"
भारत के विदेश मंत्री

सहयोग के क्षेत्र

- **द्विपक्षीय संबंध:**, भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता (IADD)
- **बहुपक्षीय:** G-20 में AU का शामिल होना
- एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC)

चुनौतियां

- अफ्रीकी देशों को **चीन द्वारा दिया जाने वाला ऋण**
- भारत द्वारा **परियोजना का मंद क्रियान्वयन**
- **समुद्री डकैती, IUU मछली पकड़ना, नशीले पदार्थों की तस्करी**

आगे की राह

- भौतिक और डिजिटल अवसंरचना में भारत का निवेश बढ़ा है
- भारत-अफ्रीका समुद्री अभ्यास की आवृत्ति में वृद्धि हुई है
- भारत को निर्यात में विविधता लानी चाहिए

4.22. भारत-मॉरीशस संबंध

भारत-मॉरीशस संबंधों का महत्व

- **द्विपक्षीय समझौते:** दोहरा कराधान परिहार समझौता (1982), द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन और संरक्षण समझौता, आदि।
- **निवेश:** उदाहरण के लिए, मॉरीशस से 161 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI (2000-2022)।
- **सांस्कृतिक और पीपल-टू-पीपल संपर्क**

चुनौतियां

- **चीन का प्रभाव:** BRI और अन्य कारणों से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति।
- **जलवायु परिवर्तन:** इससे मॉरीशस के समक्ष संकट पैदा हो रहा है।
- **अगलेगा द्वीप:** इस द्वीप पर भारतीय परियोजनाओं के कारण पर्यावरण संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो गईं।

निष्कर्ष

बदलती क्षेत्रीय भू-राजनीति को देखते हुए मॉरीशस अपनी भावी विदेश और आर्थिक नीति को निर्धारित कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए एक राह के रूप में मॉरीशस की चिंताओं से संबंधित महत्वपूर्ण पक्षों तथा SIDS के रूप में इसकी पहचान को महत्व देना होगा।

5. भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव (Effect of Policies and Politics of Developed and Developing Countries on India's Interests)

5.1. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव - दसवीं वर्षगांठ

BRI से जुड़ी चिंताएं

- **ऋण जाल**
- **कार्यान्वयन के क्रम में कई समस्याएं** (भ्रष्टाचार संबंधी घोटाले, लोगों का विरोध)
- **पर्यावरणीय जोखिम**
- **भारत की चिंताएं**
  - भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन
  - भारत का प्रभाव कम हो रहा है

BRI की प्रतिक्रिया में शुरू की गई प्रमुख पहलें

- **'पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट' (PGII)**
- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) पहल**
- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)**
- **एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC)**

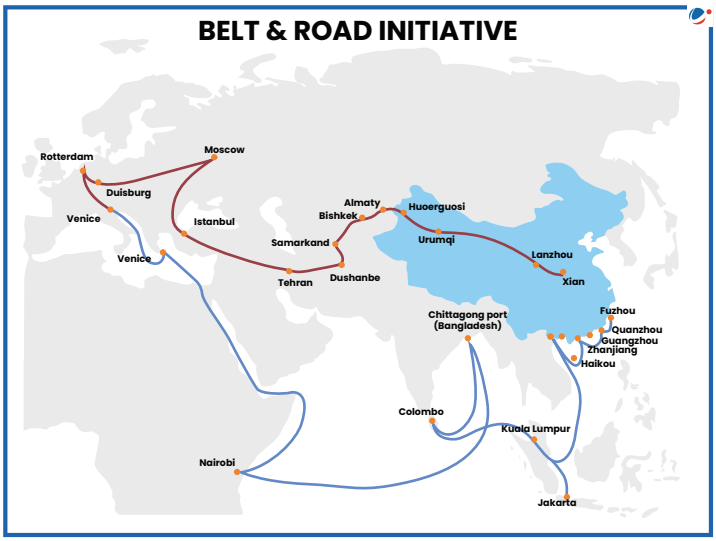

5.2. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)

चीन और पाकिस्तान ने **CPEC के तहत सहयोग में तेजी लाने के लिए छह समझौते किए।**

भारत के लिए चिंता

- **संप्रभुता:** CPEC भारत की स्वीकृति के बिना PoK से होकर गुज़रता है
- **रणनीतिक:** CPEC में निवेश से चीन को भारत के खिलाफ कम लागत पर एक डिटरेंट के रूप में पाकिस्तान का उपयोग करने में मदद मिल सकती है।
- **सुरक्षा:** सीमा-पार आतंकवाद और अवैध तस्करी की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** चीन पर पाकिस्तान की निर्भरता को बढ़ाते हैं।

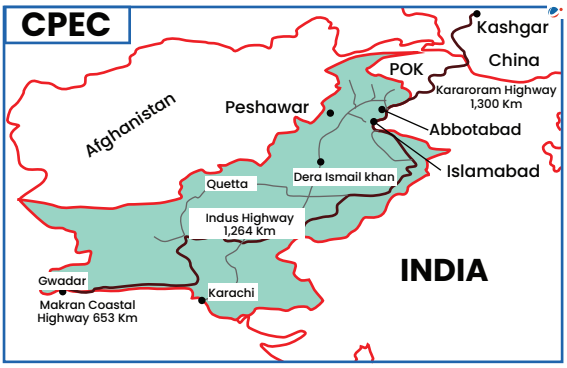

आगे की राह

- चीन और पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक प्रयास करना चाहिए
- ब्लू डॉट नेटवर्क जैसी क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए

5.3. नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO)

हाल ही में, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो/ NATO) ने अपने गठन के **75 वर्ष** पूरे किए। साथ ही, **स्वीडन** आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल होने वाला 32वां सदस्य बन गया है।

नाटो के पूर्व की ओर विस्तार के प्रभाव

- रूस और पश्चिम के बीच **अविश्वास पैदा करना**
- **यूरोप में मौजूदा विभाजन** को तीव्र करना
- यूरोप में **सैन्यीकरण** में वृद्धि

नाटो के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

- **वित्त-पोषण की समस्या**
- पूरे यूरोप में **दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद** का प्रसार हो रहा है
- **संयुक्त राज्य अमेरिका की** यूरोप की रक्षा के प्रति **प्रतिबद्धता**
- **रूसी आक्रामकता**
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति

निष्कर्ष

नाटो को जटिल भू-राजनीतिक वास्तविकताओं से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता के स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका को बनाए रखना होगा। इसके लिए नाटो को नवाचार, लोचशीलता और रणनीतिक दूरदर्शिता की एक व्यापक रणनीति को अपनाना होगा।

5.4. ऑकस

AUKUS सदस्य (ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) **उन्नत क्षमताओं वाली परियोजनाओं** को लेकर **जापान के साथ सहयोग** पर विचार कर रहे हैं।

AUKUS से संबंधित चिंताएं

- AUKUS के आधिकारिक **वक्तव्यों** और रणनीतिक उद्देश्य में स्पष्टता का अभाव है
- **हिंद-प्रशांत में तनाव: चीन, AUKUS का विरोध करता है।**
- **AUKUS क्वाड से अलग है:** AUKUS क्वाड के विपरीत रक्षा साझेदारी को प्राथमिकता देता है।

भारत और AUKUS

भारत के लिए AUKUS का महत्व

- क्वाड का पूरक
- फ्रांस के साथ रणनीतिक सहयोग

भारत के लिए चिंताएं

- भारत के क्षेत्रीय प्रभाव में संभावित कमी आ सकती है
- AUKUS संभावित रूप से हिंद-प्रशांत में शक्ति संतुलन को बदल सकता है

6. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश (IMPORTANT INTERNATIONAL INSTITUTIONS, AGENCIES, AND FORA, THEIR STRUCTURE, MANDATE)

6.1. बदलते समय में वैश्विक संस्थाएं

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे प्रमुख वैश्विक संस्थान **अपने वांछित उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं।** इस कारण इन संस्थाओं में व्यापक सुधारों की मांग उठ रही है।

समकालीन मुद्दे और वैश्विक संस्थाओं की सीमाएं

- **पश्चिमी आधिपत्य नियंत्रण,** वीटो शक्ति का दुरुपयोग
- **वैकल्पिक मंचों का उदय, जैसे-** G20, G7 और BRICS आदि
- **बढ़ते संघर्ष:** रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष
- **निष्क्रिय विवाद निपटान प्रणालियाँ:** उदा. विश्व व्यापार संगठन

वर्तमान वैश्विक संस्थाओं की प्रासंगिकता और महत्त्व

- **लगभग सभी देश सदस्य के रूप में:** जैसे कि UN-193, IMF-190 आदि। इतनी अधिक सदस्यता इन संस्थाओं में वैश्विक विश्वास को दर्शाती है।
- **वैश्विक शांति के संरक्षक:** 1948 से ही UN ने कंबोडिया, मोजाम्बिक आदि में कई संघर्षों को समाप्त करने में मदद की है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने एवं विनियामक के तौर पर:** जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और UNHRC जैसी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने एवं विनियामक के रूप में कार्य करती हैं।
- **वैश्विक वित्तीय स्थिरता:** IMF और विश्व बैंक ने कई अवसरों पर देशों (भारत सहित) को उनके संकट के समय समर्थन दिया है।
- **वैश्विक विकास को दिशा देना:** UN की ओर से SDGs जैसे लक्ष्य सामूहिक विकास को दिशा प्रदान करते हैं।

आगे की राह

- **गवर्नेंस में व्यापक परिवर्तन:** उदाहरण के लिए- भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
- **वित्तीय सुधार:** जैसे निजी निवेश बढ़ाना।
- समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) जैसी **संस्थाओं को सशक्त बनाना।**
- **प्रौद्योगिकी को अपनाना:** AI, उपग्रह निगरानी और डिजिटल डेटा संग्रह, जलवायु संकट।

6.2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: एक नज़र में

UNSC में सुधार की आवश्यकता

पुरानी संस्था: अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से कोई स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं।

प्रतिबंध लगाकर राष्ट्रों की **संप्रभुता का अतिक्रमण करना**

वीटो शक्तियां: वीटो शक्तियों का उपयोग करके प्रमुख निर्णयों को रोक दिया जाता है।

UNSC में भारत का योगदान

भारत ने 'तालिबान तथा लीबिया प्रतिबंध समितियों' की अध्यक्षता की

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) को तैयार करने में योगदान दिया

संयुक्त राष्ट्र में रंगभेद का मुद्दा उठाने वाला पहला देश

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सैनिकों का सबसे बड़ा प्रदाता

भारत के समक्ष चुनौतियां

- आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति का अभाव
- कोविड-19 के बाद की विश्व व्यवस्था
- बहुपक्षीय कूटनीति के लिए संसाधनों की कमी

6.3. भारत और यू.एन. पीसकीपिंग यानी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना

इंडियन आर्मी ने **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना** की शुरुआत की **76वीं वर्षगांठ** मनाई।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान

- भारत ने शांति स्थापना मिशनों में **2,87,000** के आस-पास सैनिकों की सेवाएं प्रदान की हैं।
- भारत **लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार पर ट्रस्ट फंड में योगदान देने वाला पहला देश था।**
- पूर्ण महिला सैन्य टुकड़ी तैनात करने वाला प्रथम देश।
- इंडियन आर्मी ने प्रति वर्ष 12,000 से अधिक सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (CUNPK)** की स्थापना की है।

संगठनात्मक चुनौतियाँ

- **गैर-समावेशी**
- संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के पास **अपर्याप्त शक्तियाँ**
- **अनावश्यक मिशन**

परिचालन संबंधी चुनौतियाँ

- घटता **अंतर्राष्ट्रीय समर्थन**
- शांति स्थापित करने में **क्षेत्रीय संगठन** की भूमिका

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित सुधार

- **निर्णय लेने में** सैनिकों और पुलिस का योगदान देने वाले देशों की अधिक भूमिका
- मध्यस्थता, युद्ध विराम की **निगरानी में क्षेत्रीय संगठन का समर्थन करें**
- **शांति स्थापना मिशनों को "शुरू से ही एग्जिट रणनीति"** को ध्यान में रखना चाहिए
- **शांति सैनिकों की सुरक्षा**

निष्कर्ष

शांति स्थापना, संघर्ष से शांति की ओर कठिन मार्ग पर चलने में देशों की सहायता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पास उपलब्ध सबसे प्रभावी साधनों में से एक साबित हुई है।

6.4. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद: एक नजर में

भारत को भारी बहुमत के साथ **छठे कार्यकाल (2022-24) के लिए UNHRC में फिर से चुना गया।**

UNHRC का महत्त्व

- मानवाधिकार मुद्दे के संबंध में देशों के बीच संवाद के लिए मंच।
- **मानवाधिकार शिक्षा और सीखने को बढ़ावा देना।**
- **सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा करना।**
- मानवाधिकारों के **प्रचार और संरक्षण में नागरिक समाज की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।**

चुनौतियां

परिषद की सीटें **मानवाधिकारों का उल्लंघन** करने वाले देशों के पास रही हैं

गुटों में मतदान करने की प्रवृत्ति

गैर-बाध्यकारी सिफारिशें

आगे की राह

प्रक्रियात्मक सुधार (परिषद चुनावों में खुले मतपत्र)

राजनीतिकरण को कम करना और आम सहमति बनाना

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के **राष्ट्रीय कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना**

मानवाधिकार रक्षकों को प्रतिशोध से बचाना

निष्कर्ष

मौजूदा सुधारों, सदस्यों की जवाबदेही में वृद्धि और सहयोगात्मक प्रयासों के साथ, UNHRC दुनिया भर में मानवाधिकारों को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा दे सकता है और उनकी रक्षा कर सकता है। इससे एक अधिक न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

6.5. भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC)

भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC) के 20 वर्ष पूरे हुए।

UNCAC की सफलताएं

यह भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक **व्यापक फ्रेमवर्क** प्रदान करता है।

इसकी **अभिपुष्टि** विश्व के लगभग सभी देशों ने की है।

इसका **समीक्षा तंत्र भ्रष्टाचार-रोधी ठोस** उपायों को लागू कर रहा है।

इसने **भ्रष्टाचार-रोधी नए संस्थानों** की स्थापना और नई नीतियां बनाने में योगदान दिया है।

चुनौतियां

UNCAC **भ्रष्टाचार को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है**

UNCAC समीक्षा प्रक्रिया में **सिविल सोसाइटी को शामिल करने** की जरूरत नहीं होती है

6.6. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अभियोजक ने इजरायल के प्रधान मंत्री और हमास नेताओं पर **मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध का आरोप लगते हुए** उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की है।

ICC के अंतर्गत अपराध की 4 श्रेणियां

- **नरसंहार**
- **मानवता के विरुद्ध अपराध**
- **युद्ध अपराध**
- **आक्रामकता के अपराध**

आपराधिक न्याय के संदर्भ में ICC की सीमाएं

प्रवर्तन तंत्र का अभाव

पूर्वव्यापी क्षेत्राधिकार (Retrospective jurisdiction) का अभाव

ICC पर **पक्षपात करने का आरोप** लगाया जाता रहा है(पश्चिमी साम्राज्यवाद का उपकरण)।

ICC को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद **के अधीन करने से** इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ सकती है।	**संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती** है (ICC के गैर-पक्षकार देशों को बाध्य करने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्ति के कारण)।

भारत रोम संविधि में क्यों शामिल नहीं हुआ?

ICC का **राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग** किया जा सकता है।	**परमाणु हथियारों** और आतंकवाद को ICC के क्षेत्राधिकार **से बाहर रखा गया है।**

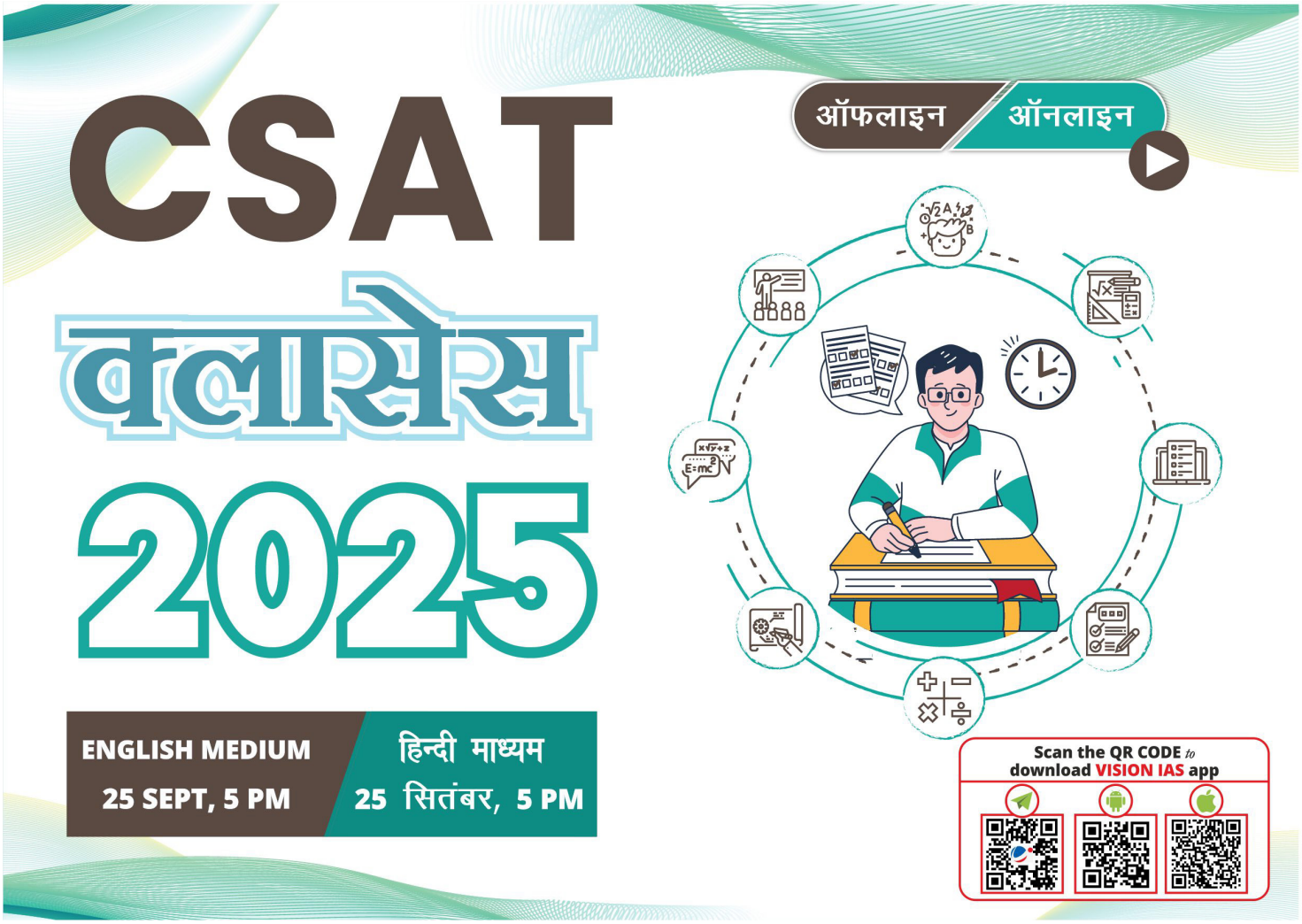

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

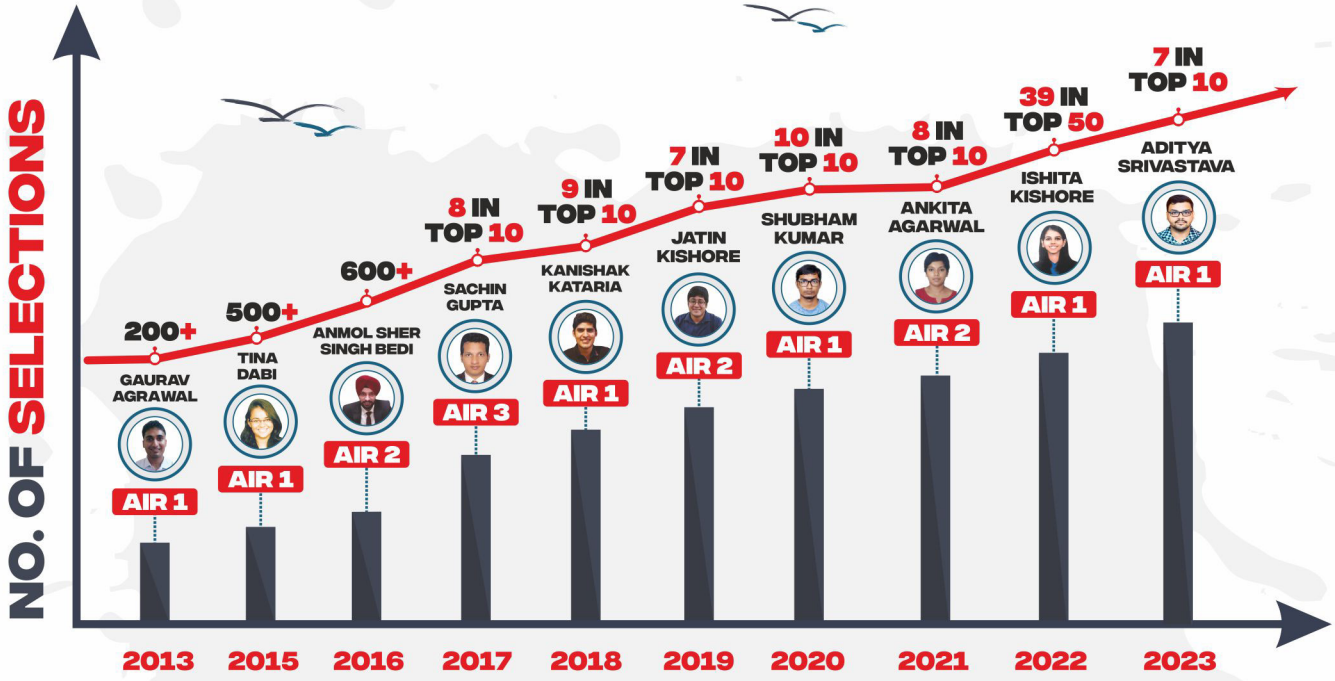

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 17 SEPT, 9 AM | 24 SEPT, 1 PM | 30 SEPT, 5 PM
27 AUG, 9 AM | 29 AUG, 1 PM | 31 AUG, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
30 AUG, 5:30 PM | 19 JULY, 8:30 AM

AHMEDABAD: 20 AUG | **BENGALURU:** 21 AUG | **BHOPAL:** 5 SEPT | **CHANDIGARH:** 9 SEPT
HYDERABAD: 11 SEPT | **JAIPUR:** 2 SEPT | **JODHPUR:** 11 JULY | **LUCKNOW:** 5 SEPT | **PUNE:** 5 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 23 सितंबर, 1 PM | 22 अगस्त, 1 PM | **BHOPAL:** 23 जुलाई | **LUCKNOW:** 18 जुलाई | **JAIPUR:** 5 सितंबर | **JODHPUR:** 11 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest Congratulations
to all Successful Candidates

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**
from various programs of **Vision IAS**

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

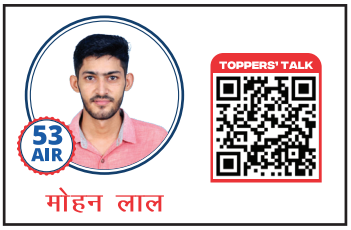

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची